2 सीटों पर मानेंगे कुशवाहा! चौराहे पर कीर्ति-शत्रु की राजनीति राजनीति की रामलीला

मूल्य : ₹ 25
नवंबर, 2018

समदिया मिथिला

राजनीति गुरु

सियासत जारी है...

कांग्रेस झामुमो तलाक तय

भाजपा से प्रेशर डील!

Best Quality *Affordable Price*

क्या इस सीजन में आप लैपटॉप लेने की योजना बना रहे हैं!

Global Computers

- DELL LAPTOP DUAL CORE
- DELL LAPTOP CORE i3
- DELL LAPTOP CORE i5,i7
- DELL "TOUCH"LAPTOPS
- DELL GAMING LAPTOP
- ASUS MINI LAPTOP 11.6"
- NOTEBOOK 15.6"
- ASUS LAPTOP i3

हर ब्रांड का लैपटॉप खरीदने के लिए

तथा डेस्कटॉप और लैपटॉप की क्वालिटी सर्विसिंग के लिए संपर्क करें.

उचित दाम और किस्तों पर भी उपलब्ध...

अधिक जानकारी के लिए 9934316573 पर संपर्क करें.

समय 10: 30 AM TO 8:00 PM (SUNDAY CLOSED)

Sushil Kumar

E-mail:- citycyber7@gmail.com

Ground Floor, Sheetal Samudra Complex, Near Bata Showroom, Lalpur, Ranchi

समदिया मिथिला
राजनीति गुरु
सियासत जारी है...
नवंबर, 2018
www. rajneetiguru.com

संपादक : राघवेंद्र
कार्यकारी संपादक : उदय कुमार चौहान
संपादक (बिहार) : प्रणव
राजनीतिक संपादक : शैलेश तिवारी
समन्वय संपादक : मनोज कुमार सिंह
प्रबंध संपादक : मुकेश मिश्रा
सहायक संपादक : कुणाल कुमार
ब्यूरो प्रमुख
मृत्युंजय श्रीवास्तव
रंजीत झा (संथालपरगना)
उमेश हेलीवाल (धनबाद कोयलांचल)
राजकुमार कुशवाहा (पाकुड़)
ऑनलाइन एडिटर : राजीव कुमार
ब्रांड एडिटर : राजीव रंजन
वरिष्ठ प्रमुख संवाददाता : प्रेमकिशोर
प्रमुख संवाददाता : श्रीधर वत्स, कुमुद रंजन
क्रियेटिव हेड : सुभाष
असिस्टेंट मैनेजर(मार्केटिंग)
पंकज मिश्रा (पटना)
विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
8405051453, 9470629387

इस अंक के कंटेंट से संबंधित प्रतिक्रिया और अपने सुझाव इमेल के जरिए भेज सकते हैं। आपके बहुमूल्य सुझाव का इंतजार रहेगा।
contact@rajneetiguru.com

मुंबई कार्यालय
504 ए विंग कृष्ण पालकी, इंद्रलोक
फेज-3 भायंदर ईस्ट, मुंबई -401102

बिहार कार्यालय
G-603, मुंडेश्वरी इनक्लेव, आशियाना रोड, पटना
स्वत्वाधिकारी, मुद्रक-प्रकाशक राघवेंद्र द्वारा बाबा प्रिंटर्स बी 46, रामनगरी, आशियाना, पटना से प्रकाशित एवं मुद्रित
सभी कानूनी मामले पटना के सक्षम न्यायालय द्वारा निपटाये जायेंगे।
आरएनआई नंबर- BIHMAI/ 2010/ 33053

इस अंक में

सियासी दांव
अकेले ही चुनाव लड़कर नया सियासी त्रिकोण बनायेगा झामुमो!
पेज » 7-11

12
पीएन सिंह ने क्यों कहा कि वह सरयू राय से छोटे हैं!
विवाद

विश्लेषण

पेज » 15
झामुमो का थ्रेट या प्रेशर पॉलिटिक्स!

सियासी यात्रा

पेज » 18
सरकार जनता के मत से चलेगी

स्याह सच

पेज » 24

हल्लाबोल

पेज » 31

सियासी घमासान

पेज » 35

अयोध्या विवाद

पेज » 43

राजनेताओं को समझना होगा युवा झारखंड का संकेत

युवा झारखंड के मन में अंतहीन सवालों का बवंडर है, पिछले 18 सालों में प्रदेश के साथ जो हुआ, उसे लेकर निराशा है लेकिन कहीं ना कहीं आबुआ राज को लेकर एक उम्मीद... एक भरोसा आज भी जिन्दा है, जो कभी बिरसायत समाज की प्रार्थनाओं में सुनाई देता है तो कभी गांधी के सच्चे अनुयायी टाना भगतों की आंखों से झांकता है। एक आशा कि कभी वो सुबह तो आयेगी।

राघवेंद्र

भाजपा के अर्जुन मुंडा ने जब झामुमो को पॉवर नहीं ट्रांसफर किया तो सरकार गिरा दी गयी और राष्ट्रपति शासन के बाद झामुमो कांग्रेस और राजद के साथ पुनः सरकार बनाने का दावा लेकर राजभवन में खड़ा था। ऐसा हुआ भी। सरकार बनी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। यह झामुमो में शिबू सोरेन युग के अवसान की भी कहानी कह गया। हेमंत का कार्यकाल भी कुछ रोड प्रोजेक्ट्स के लिए ही जाना जाता है।

झारखंड 18 वर्ष पार कर गया। 2000 में बने इस प्रदेश की तरुणाई अब सामाजिक ताने-बाने में आमूलचूल बदलाव की मांग करने लगी है। अब इस धरा-गगन को यथास्थितिवाद की चटनी नहीं चाहिए। व्यापक बदलाव से कम कुछ भी इसे स्वीकार नहीं। बदलाव से झारखंड का तात्पर्य सत्ता के अदल-बदल से नहीं है, क्योंकि इन 18 वर्षों में केवल सत्ता के चेहरे ही तो बदलते देखे हैं हमारे प्रदेश के लोगों ने। प्रदेश के करोड़ों लोगों को लगता है कि हर नया चेहरा कुछ नया गाने की कोशिश करता है, फिर खुद ही उसे मिटाता है। आमलोग अपनी अपनी उम्मीदों का ट्रांजिस्टर ऑन किये बैठे ही रह जाते हैं और उन्हें कुछ महसूस नहीं होता।

अब आप खुद ही देखिये, प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी, रोड सेक्टर पर काम शुरू किया उन्होंने, एक सकारात्मक माहौल बन ही रहा था कि डोमेसाईल की आंधी ने भाईचारे की बुनियाद ही हिला दी। फिर आये अर्जुन मुंडा, ट्राइबल- नॉन ट्राइबल के बीच की दूरी पाटने की कोशिश की लेकिन शेष चीजें यथावत रहीं। हां, अर्जुन मुंडा ने कई दशकों से रुके पंचायत चुनावों को कराया तथा पंचायतों को अधिकारसंपन्न बनाने की कोशिशें की। फिर आये शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए लेकिन विकास की पूरी गाड़ी बेपटरी हो गयी। सियासी गहमागहमी जरुर तेज़ हुई। नेताओं के नाटक को आम लोग आंख फाड़े देखते रहे, यहां तक आते आते झारखंड आयाराम -गयाराम की सियासत से भी परिचित हो रहा था। फिर आये मधु कोड़ा, लगा जैसे आधारभूत संरचना का तेज़ विकास अब संभव हो पायेगा। ऐसा कुछ हो पाता, उससे पहले ही प्रदेश सरकार के चेहरे पर भ्रष्टाचार की कालिख पुत गयी।

झारखंड के सियासी इतिहास में एक बार फिर प्रयोग हुआ। इसमें चुनाव बाद गठबंधन हुआ और झामुमो इस बार एनडीए के साथ था। तय हुआ कि आधे समय तक भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद झामुमो के। अर्जुन मुंडा सीएम बने लेकिन कालांतर में जब झामुमो ने सत्ता मांगी तो भाजपा ने पॉवर ट्रान्सफर से मना कर दिया और सरकार गिर गयी। राष्ट्रपति शासन लगना था, लगा भी। प्रदेश की नियति रही कि कई बार राष्ट्रपति शासन यहां थोपा गया।

भाजपा के अर्जुन मुंडा ने जब झामुमो को पॉवर नहीं ट्रांसफर किया तो सरकार गिरा दी गयी और राष्ट्रपति शासन के बाद झामुमो कांग्रेस और राजद के साथ पुनः सरकार बनाने का दावा लेकर राजभवन में खड़ा था। ऐसा हुआ भी। सरकार बनी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। यह झामुमो में शिबू सोरेन युग के अवसान की भी कहानी कह गया । हेमंत का कार्यकाल भी कुछ रोड प्रोजेक्ट्स के लिए ही जाना जाता है।

हेमंत के बाद जो चुनाव हुए, उसमें मोदी की आंधी का भी असर था तब भी भाजपा अपने दम पर जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाई। सुदेश महतो की आजसू के सहयोग से बनी सरकार ने झाविमो के विधायकों को तोड़ा। विधायकों की खरीद- फरोख्त का यह मामला अब भी विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चल रहा है। खैर, जैसे तैसे ही सही लेकिन झारखण्ड में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की परम्परा भी टूटी तथा रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास ने डोभा निर्माण तथा योजना बनाओ जैसे अभियान शुरू किये तथा बाहर से उद्योगपतियों को बुलाने की परम्परा तेज़ की तो लगा जैसे राज्य सरकार कुछ मौलिक कदम उठाकर लालफीताशाही खत्म कर रही है लेकिन 4 वर्ष बीतने के बाद जब अगले वर्ष सरकार चुनावों में जाने के लिए तैयार है तो जमीनी सच दावों के ठीक उलट दिखते हैं।

लालफीताशाही खत्म करने चली सरकार खुद अफ़सरों के जाल में फंसी दिख रही है। यहां दावों और हकीकत का बड़ा अंतर दिख रहा है।

आखिर इन 18 वर्षों में क्यों धुंधलाया झारखण्ड का वर्तमान! क्यों हमारा प्रदेश सरकारी लूट, खनिज लूट, बालू लूट और टेंडर घोटालों का सरमाया बनता गया। क्यों प्रदेश का कृषि क्षेत्र रसातल में पहुंच गया! क्यों किसानों को आत्महत्या जैसे अतिवादी कदम उठाने पड़े!

शिक्षा क्षेत्र का बन्टाधार करने की जिम्मेवारी किन लोगों पर है! बड़े- बड़े भवन तो खड़े हो गए लेकिन ना पर्याप्त शिक्षक बहाल हुए और ना ही शिक्षा की गुणवत्ता ही बढ़ी। ऐसा ही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का भी रहा। अस्पताल भवन बहुत सारे बनकर खड़े किये गए लेकिन डाक्टर नदारद।

आप कभी भी भेलोर गए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे झारखंड के मरीजों की भीड़ वहां दिखती है। प्रदेश में रिम्स को छोड़कर कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है, जहां मरीजों की जान की गारंटी हो।

सभी सदर अस्पताल सफेद हाथी बन चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ! यह पालिसी पैरालिसिस है। किसी भी राज्य सरकार ने कभी भी दृढ इच्छाशक्ति नहीं दिखाई और आम लोगों की जिन्दगी प्रभावित होती रही।

एक आम आदमी हर चुनाव में बड़ी उम्मीदों से अपना जन प्रतिनिधि चुनता है और उम्मीद करता है कि उसके चलने की सड़क अच्छी होगी, उसे पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। कोई अपराध होगा तो पुलिस वक्त पर पहुंचेगी। लेकिन जनप्रतिनिधि तो चुनाव जीतते ही ठेकेदारों की शरण में पहुंच जाते हैं। उनतक एक सामान्य व्यक्ति का पहुंचना कठिन हो जाता है। चुने हुए प्रतिनिधि को हर योजना के लिए तय कमीशन चाहिए। हर योजना में हिस्सा चाहिए। एक आम आदमी ठगा सा यह सब देखता रहता है और अगले चुनाव में फिर किसी और उम्मीदवार पर दांव आजमाता है, उम्मीद फिर से कि इस बार उसके दिन बदलेंगे।

हमारा पूरा तंत्र एक मकड़जाल में फंसा हुआ है। नेताओं और अधिकारियों की टीम हर दिन एक घोषणा पत्र तैयार करने में लगी रहती है। आप इन 18 सालों में की गयी घोषणाओं को जोड़ लीजिये, 10 महाभारत जैसे ग्रन्थ तैयार हो जायेंगे, लेकिन क्या इन घोषणा ग्रन्थों से राज्य की सूरत बदली! नहीं ना ...

तो फिर कैसे होगा! कैसे देश के नक्शे पर हमारा प्रदेश चमकेगा! कैसे बंद हो चुके लाखों उद्योग फिर से जीवित होंगे! कैसे लाखों बेकारों को यहीं पर काम मिलेगा! कैसे हमारी हजारों बेटियों को काम ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जीवन का तमाम नर्क नहीं देखना पड़ेगा! इन सभी प्रश्नों का जवाब है मजबूत इच्छाशक्ति । जब हमारा मुख्यमंत्री बिना किसी लाव लश्कर के किसी गांव में पहुंच जायेगा और वहां की सच्चाई से रू-ब-रू हो जायेगा, तभी से गांव और सिस्टम दोनों दुरुस्त होने लगेंगे। अभी क्या होता है, हमारे मुख्यमंत्री कहीं फील्ड विजिट का कार्यक्रम बनाते हैं, पूरा सरकारी अमला सच को छुपाने में लग जाता है। जब हमारे नेता पहुंचते हैं तो उन्हें सब ठीक लगता है। असत्य और अर्धसत्य का यही खेल तो पिछले 18 वर्षों से खेला जा रहा है।

अभी तक के सभी मुख्यमंत्री रोना रोते थे कि उनकी अल्पमत की सरकार कड़े फैसले नहीं ले सकती। अभी तो बहुमत की सरकार है, फिर हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को सच देखने से कौन रोक रहा है। अगले साल प्रदेश में चुनाव है । अभी भी सरकार के पास कुल 365 दिन हैं। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार ने जितनी भी घोषणा की है, उसके इम्पैक्ट का असेसमेंट करा लें ईमानदारी से। सब साफ हो जायेगा।

खैर, समदिया मिथिला राजनीति गुरु के इस अंक में आपको हम झारखंड और बिहार के कई सियासी कथाओं से परिचित करा रहे हैं। बिहार में सीटों को लेकर पेंच अभी भी फंसे हुए हैं। अब जदयू और भाजपा की गिरह सुलझी है तो लोजपा और रालोसपा की गांठें उलझती दिख रही है। इसकी अंतर्कथा हम आपके सामने रख रहे हैं। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस, झाविमो तथा राजद का प्रस्तावित गठबंधन बेपटरी होता दिख रहा है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कह दिया की उनका दल किसी से गठबंधन नहीं करेगा। इसके बाद कई अंतर्विरोधी स्वर सुने जाने लगे।

ऐसे संकेत आने लगे कि शायद किन्हीं सियासी मजबूरियों की वज़ह से झामुमो कांग्रेस से दूरी बढ़ा रहा है। कई किस्से दारुल सफा में गूंज रहे हैं। बहरहाल, राजनीति तो अपने आप में अन्तर्विरोध की पोटली है। इसमें कल का कुछ पता नहीं होता। क्या पता कल झामुमो भाजपा का नया गठबंधन फिर से आकार ले ले और सत्ता पर काबिज़ भी हो जाये। राजनीति का यही यथार्थ भी है कि कुछ भी स्थाई नहीं है, ना दोस्त और ना ही दुश्मन।

हमारी नज़र सभी सियासी घटनाक्रम पर है और आप पाठकों के लिए हम हमेशा नयी सियासी रपटें लेकर हाज़िर होते रहेंगे।

इस अंक पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा ।
बस, आपका ये स्नेह यूं ही हमें ऊर्जान्वित करता रहे।

कांग्रेस और झामुमो सियासी तलाक की तरफ बढ़ रहे

अकेले ही चुनाव लड़कर नया सियासी त्रिकोण बनायेगा झामुमो !

राघवेंद्र

झारखंड के सियासी गलियारे के लिए यह कोई चौंकने वाली बात नहीं है। पहले भी शिबू सोरेन कई अवसरों पर ऐसा कुछ बोलते रहे हैं जो उनके सहयोगियों को नागवार गुजरता है। कई बार ऐसा बोलने के पीछे भी कोई सियासी कहानी होती है, जिसका पता बाद में चलता है।

वह 25 अक्टूबर की दोपहर थी। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के झिलुआ पंचायत के बांसपहाड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन अपनी रौ में थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अगला विधानसभा चुनाव भी अकेली लड़ेगी। कभी -कभी गुरु जी कुछ विषयांतर भी बोल जाते हैं, इसलिए शुरू में तो उपस्थित लोगों जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे, को लगा कि शायद गुरु जी ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन शिबू सोरेन का निशाना गठबंधन ही था। उन्होंने भाजपा या राज्य सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उलटे उन्होंने तो जामताड़ा के कांग्रेस विधायक के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी।

वैसे झारखंड के सियासी गलियारे के लिए यह कोई चौंकने वाली बात नहीं है। पहले भी शिबू सोरेन कई अवसरों पर ऐसा कुछ बोलते रहे हैं जो उनके सहयोगियों को नागवार गुजरता है। कई बार ऐसा बोलने के पीछे भी कोई सियासी कहानी होती है, जिसका पता बाद में चलता है।

तो क्या झामुमो कोई ऐसी ही सियासी पटकथा तैयार कर रहा है, जिसमें भविष्य के गठबंधन सहयोगियों के लिए कोई भूमिका नहीं है या यह सहयोगी कांग्रेस पर दवाब बनाने का मास्टर स्ट्रोक भर है। दोनों ही स्थितियां गठबंधन राजनीति के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं। जो गठबंधन अभी पूरी तरह अस्तित्व में आया भी नहीं, उसके भीतर नकार भाव से भरी इतनी हांडियां पक रही हो तो खुदा ही खैर करे!

बहरहाल गुरु जी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने नपी तुली प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी दोनों मिल चुके हैं और यह गठबंधन एकजुट है, वगैरह -वगैरह। यह डरी- सहमी और सतर्क कांग्रेस की बचती - बचाती टिप्पणी थी। हालांकि गुरु जी भी 26 अक्टूबर को दुमका में अपने एक दिन पहले दिए गए बयान से पूरी तरह पलट गए और उन्होंने दाढ़ी खुजाते - खुजाते कह दिया कि हेमंत जानें कि वो किससे गठबंधन करेंगे और किससे नहीं। कई कांग्रेसी नेताओं ने तो मौके पर ही कह दिया कि गुरु जी का बयान एक प्रेशर पॉवर पॉलिटिक्स भर था।

लेकिन क्या बात इतनी सी है। जानकारों का मानना है कि झामुमो अकेले चुनाव में जाने का मन बना चुका है और अब वह किसी उचित मौके की तलाश में है, जब गठबंधन का चोला उतारकर वह फेंक देगा। गठबंधन को झटकने की पटकथा लिखी जा चुकी है और झामुमो अब आनेवाले दिनों में कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में जोर- शोर से अपना कार्यक्रम करेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर झामुमो या कांग्रेस नेता अभी इस बात को नकार रहे हैं लेकिन सारे व्यवहारिक इशारे इसी तथ्य की तरफ रौशनी कर रहे हैं।

हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता, और भविष्य की सियासत के बारे में किसी भी दल का नेता फाइनल वड्र्स नहीं लॉक कर सकता। लेकिन जिस तेज़ी से झामुमो के अंदर के गठबंधन समीकरण बदल रहे हैं, उससे यही लगता है कि पार्टी नफा - नुकसान का तेज़ी से आकलन कर रही है। वैसे भी झामुमो प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ सत्ता में भागीदारी कर चुका है, यानि चित भी मेरी और पट भी मेरी। उत्तर और दक्षिण को एक साथ साधने की विलक्षण सियासी कला में माहिर माने जाते हैं झामुमो के सूत्रधार।

राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता और भविष्य की सियासत के बारे में किसी भी दल का नेता फाइनल वड्र्स नहीं लॉक कर सकता।लेकिन जिस तेज़ी से झामुमो के अंदर के गठबंधन समीकरण बदल रहे हैं, उससे लगता है कि पार्टी नफा - नुकसान का आकलन कर रही है।

इसी कड़ी में हेमंत सोरेन ने कोल्हान के बाद दक्षिणी छोटानागपुर में अपनी संघर्ष यात्रा का रुख किया। यह जानते हुए भी कि खूंटी और लोहरदगा में झामुमो की कोई खास सियासी जमीन नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते दिखे, यह कांग्रेस को असहज करने की सोची समझी कोशिश थी, जिसमें वो सफल भी हुए और कांग्रेस असहज दिखी, हालाँकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई उकसाने वाला बयान सामने नहीं आया।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर क्या पक रहा है, जिसे लेकर इतनी पर्देदारी है।

दोनों ही दल क्या इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सियासी तलाक की पहल कोई दूसरा करे, खुद वो नहीं। क्या ऐसा अल्पसंख्यक मतदाताओं की वज़ह से किया जा रहा है! क्योंकि अल्पसंख्यक वोटरों के सामने दोनों ही उनके हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे। दोनों ही दल बदली हुई परिस्थितियों में अपने सियासी नफा-नुकसान का आकलन कर रहे हैं।

राजनीति के जानकार हेमंत की दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से हुई मुलाकात को कुछ अलग ही सन्दर्भ में देख रहे हैं, इनका कहना है कि हेमंत गए तो थे राहुल गांधी से मुलाकात करने, लेकिन उनसे मुलाकात तय दिन पर इसबार हुई नहीं और भाजपा के बड़े नेताओं ने यह मौका लपक लिया।

झामुमो के रणनीतिक सलाहकार बता रहे हैं कि कांग्रेस के बिना पार्टी ज्यादा सीटें जीतेंगी और सरकार बनाना तब आसान हो जायेगा। किसी की ब्लैक मैलिंग नहीं झेलनी होगी। लेकिन क्या बात इतनी ही सरल है, जितनी बताई जा रही है या इसके कुछ और निहितार्थ हैं, जिनका आकलन किया जाना अभी शेष है।

खैर, भाजपा के बड़े नेता इन स्थितियों पर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें लगता है कि प्रदेश की सियासी नियति उसी तरफ बढ़ रही है, जैसा वो चाहते थे। गठबंधन ने अपनी शुरुआत में ही उप चुनाव में दो सीटें जीतकर भाजपा के वोट प्रबंधकों की नींद उड़ा दी थी। ऐसे में भाजपा के बड़े नेताओं को लगने लगा था कि आनेवाले दिनों में झामुमो, कांग्रेस, झाविमो, राजद और वाम दलों की संयुक्त ताकत सत्ता विरोधी रुझान को विपक्षी खेमे की और मोड़ सकती है , अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में भाजपा की सियासी कहानी खत्म हो सकती है, इसलिए झामुमो के जरिये विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने की रणनीति बनने लगी और आहिस्ता- आहिस्ता भाजपा अपनी रणनीति में सफल होती दिखने लगी है।

झारखंड की राजनीति के जानकार हेमंत की दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से हुई मुलाकात को कुछ अलग ही सन्दर्भ में देख रहे हैं, ऐसे जानकारों का कहना है कि हेमंत गए तो थे राहुल गांधी से मुलाकात करने, लेकिन उनसे मुलाकात तय दिन पर इसबार हुई नहीं और भाजपा के बड़े नेताओं ने यह मौका लपक लिया। हेमंत के दिल्ली से लौटने के बाद उनके बयान भी सत्ता के खिलाफ थोड़े कम आक्रामक हुए हैं। भाजपा के ही कुछ लोग इस पूरी सियासी कहानी को कुछ महीने पहले के केंद्र सरकार के बड़े फैसले से जोड़कर देख रहे हैं, जिसके बाद कई दलों के नेता आयकर के रडार पर आ गए थे। खैर सियासत की वो कहानी अक्सर सच नहीं होती जो नेता लोग ऑफ द रिकॉर्ड चटखारे लेकर मीडिया से साझा करते हैं, कहानी वो सच होती है जो नेता लोग अपने अन्तःपुर से बाहर नहीं आने देते। इसबार भी माजरा कुछ ऐसा ही लग रहा है।

बताया जाता है कि भाजपा की नरमदिली के अलावा बाबूलाल प्रकरण भी इस मामले में एक त्रिकोण है। हेमंत हमेशा से कांग्रेस द्वारा जेवीएम को ज्यादा तरजीह दिए जाने के खिलाफ थे।

सुदेश महतो की आजसू ने एनडीए से बाहर आने का फैसला कर ही लिया है। अगर पार्टी अपने उहापोह को छोड़कर कांग्रेस और झाविमो के साथ जाने का फैसला करती है तो आजसू को भी सियासी बैटिंग के लिए बेहतर पिच मिलेगी।

बाबूलाल ने कभी भी पहले हेमंत सोरेन को अपना नेता नहीं माना था, वो तो कांग्रेस ने अपनी ओर से पहल कर जेवीएम और इसके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को इस बात के लिए तैयार किया था कि गठबंधन राजनीति में वास्तविक संख्या गणित के आधार पर झामुमो को बड़े भाई की हैसियत मिलनी ही चाहिए। मौके की नजाकत को देखकर मन मारकर बाबूलाल इस बात पर तैयार हो भी गए।

इसके बाद राहुल गांधी से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात भी हुई। पहले भी राहुल गांधी झारखंड के नेताओं में मरांडी को सम्मान की नज़र से देखते रहे हैं। शायद बाबूलाल को कुछ ज्यादा सम्मान दिए जाने से भी हेमंत असहज थे। कुछ समय पहले झामुमो के एक नेता की ओर से कांग्रेस के एक बड़े नेता को बताया भी गया था कि अब बाबूलाल मरांडी जी की क्या वास्तविक ताकत बची है जो कांग्रेस उन्हें सियासी तौर पर पुनर्जीवित करने में जुटी हुई है। हालांकि पिछले चुनावों के पहले बाबूलाल मरांडी ने ऐन वक्त पर कांग्रेस से अपना रास्ता अलग चुन लिया था।

अब आगे क्या होगा! इसपर बिना किसी शोर के झामुमो और कांग्रेस के रणनीतिकार माथापच्ची कर रहे हैं। एक -एक सीट का आकलन किया जा रहा है। संभावित उम्मीदवारों पर डोरे डाले जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष के उम्मीदवार बेहद सतर्कता से सब कुछ देख रहे हैं और क्षेत्र के लोगों का मूड भांप रहे हैं। कई झामुमो उम्मीदवार कांग्रेस तो कई कांग्रेस उम्मीदवार झामुमो की तरफ खिसक सकते हैं। जिस साझी ताकत का इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ होना था, वो बम बारूद विपक्ष के ही बड़े नेताओं पर फोड़ने की तैयारी है। अल्पसंख्यक मतदाता अभी खामोश हैं, क्योंकि वो अपने पत्ते सबसे आखिर में खोलते हैं। अल्पसंख्यकों को पता है कि जो भाजपा को हराएगा उसके साथ ही गोलबंदी होनी है।

ऐसे में अब सबकी नज़र आजसू की ओर भी है। अगर झामुमो इस गठबंधन से अलग हुआ तो आजसू को झामुमो की जगह कांग्रेस और झाविमो के साथ लाने की कोशिशें की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को फायदा ही होगा। उसके जीतने वाले सीटों की संख्या 12-13 से बढ़कर 18-19 तक जा सकती है। क्योंकि तब कांग्रेस गठबंधन के पास बाबूलाल मरांडी के रूप में एक बड़ा चेहरा होगा, जिनका हर विधानसभा में अपना फिक्स वोट है, सुदेश महतो के रूप में प्रदेश का सबसे बड़ा बैकवर्ड चेहरा होगा और कांग्रेस के नाम पर अल्पसंख्यक वोट बैंक भी साथ आ सकता है।

यह सही है कि संथाल और कोल्हान में झामुमो के साथ आदिवासी वोट ताकत से खड़ा है, जो अभी भी शिबू सोरेन को ही अपना नेता मानता है। लेकिन दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर और पलामू के अलावा संथाल के कुछ हिस्सों में आदिवासी युवाओं के बीच मरांडी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आयी है।

सुदेश महतो की आजसू ने एनडीए से बाहर आने का फैसला कर ही लिया है। अगर पार्टी अपने उहापोह को छोड़कर कांग्रेस और झाविमो के साथ जाने का फैसला करती है तो आजसू को भी सियासी बैटिंग के लिए बेहतर पिच मिलेगी, आजसू अपने सीटों की तादाद में तो इजाफा करेगी ही साथ ही कुर्मी जाति के अलावा सुदेश महतो प्रदेश के सबसे बड़े पिछड़े चैंपियन के रूप में स्थापित हो सकते हैं। यह स्थापना आजसू की स्वीकार्यता को स्थाई रूप से बढ़ा सकती है और उसे एक नया जनाधार दिला सकती है। ऐसे में आजसू दहाई के आंकड़े को भी छू सकती है।

इसके अलावा राजद के साथ होने से यादव वोट बैंक भी इस गठबंधन के ही नैसर्गिक रूप से साथ होगा। झारखंड की पिछड़ी आबादी में कुर्मी के बाद यादव ही सबसे बड़ा फैक्टर है। यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी जमाने में इस इलाके से राजद के 7 विधायक तक रहे हैं यानि सात ऐसी सीटें हैं जहां यादव वोटर हार -जीत का फैसला कर सकते हैं।

इस प्रस्तावित गठबंधन में वाम दल किधर होंगे, यह देखना भी दिलचस्प होगा। कल्पना करिये, अगर झारखंड विधानसभा के चुनाव में एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ झामुमो और तीसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन बना तो निश्चित तौर पर माले को छोड़कर सीपीआई, सीपीएम और मासस जैसी वाम पार्टी कांग्रेस नीत मोर्चा में सहज महसूस करेगी। अगर सम्मानजनक और जीतने लायक सीटों का यथार्थ बंटवारा हुआ तो कम से कम 4 सीट लाने की क्षमता वाम दलों में भी है। फिर ये समीकरण पूरे चुनावी परिदृश्य को ही मजेदार बना देंगे।

बहरहाल, हम फिर एकबार पुराने सवाल पर लौटते हैं कि आखिर जिस गठबंधन ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा को थामा, जिसने सिल्ली और गोमिया में एनडीए के जबड़े से जीत छीना, वह कुछ ही महीनों में सियासी तलाक की तरफ कैसे बढ़ रहा है ! महत्वाकांक्षाओं के बोझ से सबके गर्दन इतने कैसे दब गए कि वास्तविक सियासी खतरे को ही इन सभी ने नज़रंदाज़ कर दिया। ये व×क्त था अपनी साझा ताकत से सत्ता विरोधी रुझान को गोलबंद करने का और ये आपस में ही शर्तें रखने लगे। एक दूसरे सहयोगी दल के नेताओं को तोड़ने की फिराक में लग गए ।

अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय पूरी शिद्दत से झामुमो को गठबंधन में रखने के लिए कोशिश करते दिख रहे हैं। इससे हालांकि कांग्रेस पार्टी की झामुमो की बी टीम वाली छवि बन रही है, जिसका खुद कांग्रेस के ही कई नेता विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि डॉ अजय अपनी एक जमशेदपुर सीट जीतने के लिए पूरी पार्टी के सम्मान से ही समझौता कर रहे हैं।

अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय पूरी शिद्दत से झामुमो को गठबंधन में रखने के लिए कोशिश करते दिख रहे हैं। इससे हालांकि कांग्रेस पार्टी की झामुमो की बी टीम वाली छवि बन रही है, जिसका खुद कांग्रेस के ही कई नेता विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि डॉ अजय अपनी एक जमशेदपुर सीट जीतने के लिए पूरी पार्टी के सम्मान से ही समझौता कर रहे हैं।

अब आरोप-प्रत्यारोप का सच तो कांग्रेस और झामुमो के नेता ही जानें, लेकिन जितनी जल्दी गठबंधन पर से महत्वाकांक्षाओं की धुंध हटे, उतना ही सबके लिए बेहतर। शायद प्रदेश की राजनीति के लिए भी।

धनबाद लोकसभा सीट से टिकट की कहानी

पीएन सिंह ने क्यों कहा कि वह सरयू राय से छोटे हैं!

अमित राजा

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

मंत्री सरयू राय ने भले ही कह दिया कि उनकी इच्छा धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन खुद को उन्होंने मौजूदा सांसद पीएन सिंह से उम्र में छोटा होने की बात कर लोगों को संशय में भी डाल दिया।

आम चुनाव 5-6 महीने बाद होने हैं, मगर धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट पाने के लिए अखाड़ा अभी से सज गया है। इस अखाड़े पर भाजपा के कई दिग्गज दिलचस्प दंगल में भिड़ गये हैं। इस लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व करने का ख्वाब पाले धनबाद नगर निगम के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और मौजूदा सांसद पीएन सिंह के बीच बयानबाजी पुरानी बात हो गयी।

धीरे -धीरे पुराने कार्यकर्ताओं को इस बयान युद्ध की आदत सी पड़ गयी. लेकिन, पिछले 25 दिनों के अंदर तेजी से सियासी घटनाक्रम बदले हैं और टिकट पाने की रेस में सूबे के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के बाद धनबाद की पूर्व सांसद प्रो रीता वर्मा और झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह भी कूद पड़ी हैं। ऐसे संकेत इन दिग्गजों के बयानों और उनकी गतिविधियों से ही सामने आये हैं।

मंत्री सरयू राय ने इस बाबत पूछे जाने पर भले ही कह दिया कि उनकी इच्छा धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन खुद को उन्होंने मौजूदा सांसद पीएन सिंह से उम्र में छोटा होने की बात कर लोगों को संशय में भी डाल दिया। दरअसल, भाजपा में उम्र दराज सांसदों का टिकट कटने की बात उछलने के बाद से दूसरे कई महत्वाकांक्षी नेताओं के अरमान मचले हैं। हालांकि सरयू राय ने बातचीत में कहा कि 'मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें कहां से उठ रही हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिम में भी ऐसी बातें विरोधी उछाल रहे हैं कि मैं धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करता है।

कोयलांचल में 14 सालों से सरयू सक्रिय

दामोदर बचाओ अभियान के तहत सरयू राय कोई 14 सालों से धनबाद और बोकारो की राजनीति में सक्रिय हैं। वे हरेक साल दामोदर नदी में गंगा दशहरा मनाने पहुंचते रहे हैं लेकिन, अचानक इन दिनों उनकी सक्रियता बढ़ी है। दो-तीन दौरे तो हर महीने इस लोकसभा क्षेत्र के कर रहे हैं। सामाजिक और सियासी लोगों के घर जाकर वे टी और लंच पॉलिटिक्स में रमे हैं। वे कई मुद्दों पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भी धनबाद पहुंचते हैं। जो हो, सरयू राय की इस सक्रियता से पीएन सिंह असहज जरूर हैं, क्योंकि इस बाबत सरयू राय को लेकर उनके बयान आ चुके हैं।

सरयू को रघुवर के ग्रीन सिग्नल की चर्चा

भाजपा की छोटी-बड़ी कमेटियों में यह बात चर्चा में है कि सरयू राय को मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी सिग्नल मिल चुका है। पार्टी लाइन से हटकर वे अपनी राय रखते रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोलने से भी वे गुरेज नहीं करते। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं। उनकी इच्छा संसद के अंदर पहुंचने की है। लिहाजा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं । सरयू राय ही एक मात्र नेता हैं जो सरोकारी मसलों पर सरकार के खिलाफ भी सख्त हो जाते हैं। ऐसे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चाहते हैं कि सरयू राय लोकसभा का चुनाव लड़ें और जीत कर दिल्ली चले जायें। इस तरह सरयू राय दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हो जायें तो झारखण्ड भाजपा के कई नेताओं को चैन मिलेगा. बस यहीं से सरयू के दिल्ली सफर की चर्चा तेज़ हो गयी.

सरयू राय ही एक मात्र नेता हैं जो सरोकारी मसलों पर सरकार के खिलाफ भी सख्त हो जाते हैं। ऐसे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चाहते हैं कि सरयू राय लोकसभा का चुनाव लड़ें और जीत कर दिल्ली चले जायें।

राजनीतिक जानकार धनबाद सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीएन सिंह को रघुवर दास के विरोधी खेमे में बताते हैं। इसलिए रघुवर धनबाद से लोकसभा का चुनाव सरयू को लड़ाकर दो तरफा निशाना साधने की बातें हवा में तैर रही है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री भी उतरीं मैदान में

धनबाद लोस सीट से टिकट की टिक-टिक में धनबाद लोकसभा क्षेत्र से तीन बार लगातार सांसद और एक बार केंद्रीय मंत्री रहीं अशोक चक्र से सम्मानित शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की पत्नी प्रो. रीता वर्मा भी शामिल हो चुकी हैं। सियासत में कुछ सालों की निष्क्रियता के बाद और कॉलेज से अवकाश लेने के बाद वे सक्रिय हो गयीं हैं। दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन समेत छोटे-मोटे कार्यक्रम के बाद पूर्व सांसद प्रो. रीता वर्मा ने झरिया थाना मोड़ पर सरदार बल्लभ भाई पटेल समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वर्षों बाद पहली बार राजनीतिक भाषण दिया।

धनबाद की दुर्दशा के कारणों का उत्तर देने की कोशिश की। जन प्रतिनिधि को इसके लिए जिम्मेवार बताया। पूछा कि धनबाद में उनसे ज्यादा काम किसने किया? संसद में कई सवाल तक नहीं पूछ पाये। मैंने एमपीएल बनवाया। इसके बाद धनबाद में इतना बड़ा कोई उद्योग नहीं लगा। एक निरसा और एक बोकारो में नवोदय विद्यालय व क्षेत्र में पांच केंद्रीय विद्यालय खुलवाये।

धनबाद को एक मेगावाट बिजली दिलाई। प्रो. वर्मा ने कहा कि पार्टी ने अगर टिकट दिया तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगी। वह टिकट की दावेदार हैं।

पीएन सिंह के मुताबिक अभी उनकी उम्र 70 वर्ष भी नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैं सरयू राय से छोटा हूं। जबकि सरयू राय ने कहा कि कम उम्र वाले भी तो बीमार होते हैं। जबकि बड़े उम्र वाले भी स्वस्थ हो सकते हैं। बकौल सरयू राय 'मैं तपस्या रत हूं। दामोदर को साफ और जिंदा करने में लगा हूं।

पीएन, रीता व सरयू ने दी उम्र पर सफाई

टिकट देने के मामले में उम्रदराज नेताओं को किनारा लगाने की उड़ी भाजपा में खबर से सांसद पीएन सिंह असहज हैं। उनकी नींद सरयू राय और रीता वर्मा की सक्रियता देखकर भी उड़ गयी है। पीएन सिंह के मुताबिक अभी उनकी उम्र 70 वर्ष भी नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैं सरयू राय से छोटा हूं। जबकि सरयू राय ने कहा कि कम उम्र वाले भी तो बीमार होते हैं। जबकि बड़े उम्र वाले भी स्वस्थ हो सकते हैं। बकौल सरयू राय 'मैं तपस्या रत हूं। दामोदर को साफ और जिंदा करने में लगा हूं। ऋषि मुनियों की तपस्या को देख इंद्र को लगता था कि उनका सिंहासन खतरे में है, उसी तरह मुझसे भी कुछ लोग शायद दहशत में हैं।

मंत्री सरयू राय को पीएन सिंह ने उम्र में खुद से बड़ा बताया है, इस पर सब जानना चाहते हैं कि दोनों में किनकी उम्र अधिक है। इधर भाजपा नेता कृष्णा अग्रवाल ने इंडिया.गव.इन पोर्टल पर दर्ज ब्योरे के हवाले से कहा कि सांसद पीएन सिंह की जन्म तिथि 11 जुलाई 1949 है। जबकि सरयू राय की जन्म तिथि 16 जुलाई 1951 है। इस तरह उम्र में पीएन सिंह मंत्री सरयू राय से दो वर्ष बड़े हैं। बहरहाल, उम्र के इस जंग में प्रो रीता वर्मा भी कूद पड़ी हैं। प्रो वर्मा ने कहा कि उनकी उम्र भी धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़कर जीतनेवालों से कम है। वह धनबाद के सांसद के रूप में अंतिम पारी खेलना चाहेंगी।

कुंती सिंह के कूदने से दंगल हुआ दिलचस्प

झरिया विधायक संजीव सिंह की मां पूर्व विधायक कुंती सिंह भी धनबाद सीट से टिकट दंगल में शामिल हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से थोपा गया प्रत्याशी हमें स्वीकार नहीं होगा। सिंह मैंशन लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि बाहरी प्रत्याशी को लेकर कुंती सिंह का बयान पीएन सिंह के लिए राहत भरी भी है।

उनके इस बयान से टिकट के दूसरे दावेदारों को भी बल मिला है। सांसद पीएन सिंह का टिकट कटने की स्थिति में ऐसे दावेदार खुद के लिए गोटी सेट करने में जुट गए हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य कुंती सिंह कहती हैं कि सांसद पीएन सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो सिंह मैंशन टिकट की दावेदारी करेगा। धनबाद के किसी भी भाजपाई को टिकट मिले तो कोई विरोध नहीं है।

दक्षिणी छोटानागपुर के कांग्रेसी किले में हेमंत की संघर्ष यात्रा

थ्रेट या प्रेशर पॉलिटिक्स !

रवीन्द्र के मिश्र

लोकसभा चुनाव की धमक अब रांची छोड़ दक्षिणी छोटानागपुर के चार जिले गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी के सियासी कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुकी है। सत्ता विरोधी मुहिम को धार देने के लिए राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब आदिवासी बहुल इन जिलों का रूख किया है। कांग्रेस और झामुमो के बड़े नेताओं ने अपने सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं में जान डालने के लिए उनसे सीधे मुखातिब हो मंत्रणा करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है।

कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमंडलस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर कांग्रेसियों में लोस चुनाव को लेकर जोश भरने का कार्य तेज़ कर दिया गया है . इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा अजय कुमार ने साधारण कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान देने का भरोसा दिलाया। वहीं झामुमो नेता हेमंत सोरेन संघर्ष यात्रा के माध्यम से गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी जिलों के नेताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के प्रयास में जुटे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोहरदगा एवं खूंटी संसदीय सीट कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मन जाता है, क्योकि उक्त दोनों ही सीटों पर कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी रही है।

झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने भी संघर्ष यात्रा के बहाने लोहरदगा एवं खूंटी लोक सभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में दौरा कर भाजपा विरोधी वोट बैंक को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की हितैषी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है।

कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं एवं वोटरों को भी ऐसा ही स्पष्ट संदेश दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में इन क्षेत्रों से उनकी वापसी तय है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक अपने कार्यकताओं को यह फार्मूला नहीं बताया है कि भाजपा विरोधी मतों के बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति है, क्योंकि वोटों का बिखराव ही कांग्रेस के हार का कारण होता है।

दूसरी ओर झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने भी संघर्ष यात्रा के बहाने लोहरदगा एवं खूंटी लोक सभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में दौरा कर भाजपा विरोधी वोट बैंक को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की हितैषी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। वैसे भी झामुमो अध्यक्ष की सियासी बयानबाजी से राज्य में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बनने के पूर्व ही झामुमो की धमकी से भहरता हुआ दिख रहा है।

ऐसे में कांग्रेस इन दोनों संसदीय सीटों पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को कैसे मजबूत रखेगी, इसको लेकर विमर्श जारी है। उधर झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन की संघर्ष यात्रा में जनता से उनका सीधा संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों में आम सभाओं में उमड़ी भीड़ एक अलग समीकरण की ओर संकेत कर रहा है। हेमंत सोरेन का दक्षिणी छोटानागपुर की यात्रा आगामी लोकसभा एवं भावी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले की करीब एक दर्जन से अधिक जनसभाओं में उमड़ी उत्साही भीड़ और कांग्रेस के निष्प्रभावी कार्यकर्ता सम्मेलन के निहितार्थ झामुमो के लिए उत्साहजनक हैं ।

हेमंत सोरेन अपनी जनसभाओं में आदिवासी एवं मुस्लिम तथा इसाई वोटरों को यह समझाने में काफी सफल रहे हैं कि भाजपा की सरकार आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विरोधी है।

सूत्रों की मानें तो हेमंत सोरेन अपनी जनसभाओं में आदिवासी एवं मुस्लिम तथा इसाई वोटरों को यह समझाने में काफी सफल रहे हैं कि भाजपा की सरकार आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विरोधी है। इसे हटाने के लिए चुनाव में एकजुटता बहुत आवश्यक है। हेमंत सोरेन इन क्षेत्रों में जनता के साथ-साथ समुदाय विशेष के धार्मिक प्रमुखों से भी संपर्क कर राज्य के हालात पर विमर्श किया है। सूत्र यहां तक बताते है कि इस यात्रा में हेमंत सोरेन ने जनसभाओं से कम अहमियत बिशप एवं पादरियों को नहीं दिया है। हेमंत सोरेन की सभा में जिला मुख्यालय गुमला को छोड़कर सभी स्थानों पर भारी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित हुए।

इससे यह अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि छोटानागपुर के ग्रामीण इलाकों में विकास को लेकर सरकार की लोक लुभावन बयानबाजी ने ग्रामीणों को प्रभावित नहीं किया है। इसके विपरित मुस्लिम, आदिवासी और इसाई समुदाय के लोगों में यह संशय मजबूत हुआ है कि वर्तमान सरकार के कारण उनके अस्तित्व पर खतरा है। इसलिए हर हाल में इसे हटाने के लिए भाजपा विरोधी मतों के बिखराव को रोकना है। भले ही देश के स्तर पर सियासी दलों का आपसी समन्वय न हो किंतु आदिवासियत की सुरक्षा के लिए छोटानागपुर में किसी एक के पक्ष में ही यहां के मूलवासी एकजुट होंगे।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे संसाधनों की मांग

गुमला में संपन्न कांग्रेस के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में ओज भरने का भरसक प्रयास किया। इसके लिए सरकार की नाकामियों को अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। किंतु कार्यकर्ताओं ने कमजोर संगठन होने के कमजोर रगों पर भी चोट किया। सत्ता से विलग होने के बाद छोटे कार्यकर्ताओं की नेताओं के द्वारा उपेक्षा और आपसी गुटबाजी के शिकार कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता जिन पर पंचायत एवं बूथस्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेवारी है। वे स्वयं को इस काम के लिए लाचार एवं साधनहीन मानते हुए संगठन से साधन मुहैया कराने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में यहां के मूलवासियों की जनभावनाओं पर खरा उतरना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है।

झामुमो को छोटानागपुर में खोने को कुछ नहीं

हेमंत सोरेन की दक्षिणी छोटानागपुर में निकाली गई संघर्ष यात्रा विपक्षी महागठबंधन के मुगालते में रहनेवाले कांग्रेस के लिए एक सबक का संकेत है। क्योंकि लोकसभा के लिहाज से झामुमो के पास यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हेमंत सोरेन का व्यक्तित्व यहां के मूलवासियों को भाने लगा है। वर्तमान में दोनों लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा सीटों में से मात्र एक बिशुनपुर पर झामुमो के विधायक हैं। पिछले लोक सभा चुनाव में वर्तमान झामुमो विधायक चमरा लिंडा का निर्दलीय खड़ा होना ही कांग्रेस प्रत्याशी की हार एवं भाजपा की जीत का कारण बना था। इस लिहाज से लोस चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन की दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में इंट्री विपक्षी एकजूटता को प्रभावित करने के साथ- साथ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है।

कांग्रेस को अपने मजबूत आधार वाले खूंटी व लोहरदगा लोस सीटों पर भी झामुमो के विश्वासघाती कदम से नुकसान हो तो कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी। क्योंकि जीत का दारोमदार तो भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने पर है।

हेमंत की इंट्री कांग्रेस पर दबाव के लिए तो नहीं?

लोकसभा के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम प्रत्याशी की घोषणा की जिद पर अड़े जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दक्षिणी छोटानागपुर के जिलों में यात्रा निकालने के पीछे जेएमएम का कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। क्योकि कांग्रेस नेतृत्व वर्ष 2019 के लोक सभा चुनाव में मोदी को हटाने के लिए बड़ा दिल रखने की रणनीति पर झारखंड में भी काम कर रही है। किंतु यदि इसमें कांग्रेस को अपने मजबूत आधार वाले खूंटी व लोहरदगा लोस सीटों पर भी झामुमो के विश्वासघाती कदम से नुकसान हो तो कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी। क्योंकि जीत का दारोमदार तो भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने पर है। इसलिए लोगों का यह भी मानना है कि हेमंत सोरेन खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में यात्रा कर कांग्रेस को यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि उनकी मजबूत पकड़ आदिवासी बहुल छोटानागपुर पर भी है। जिसे कांग्रेस अपना परंपरागत सीट होने का दावा करती है।

अब झामुमो की इस अप्रत्यक्ष चेतावनी पर कांग्रेस कितना संभलती है और क्या कदम उठाती है, यह तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर है। लेकिन भाजपा विरोधी मतदाताओं के बीच इस बात की चर्चा होने लगी है कि कहीं ऐन मौके पर झामुमो विपक्षी गठबंधन को लंगड़ी मारने की तैयारी तो नहीं कर रहा। इस बात पर कांग्रेस नेता तो अभी बहुत सम्हलकर बोल रहे हैं लेकिन झामुमो की मुद्रा आक्रामक है।

सरकार जनता के मत से चलेगी सियासतदानों के मन से नहीं

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सुदेश महतो सूबे के हर इलाके में जा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, कोशिश है कि संवाद दोनों ही ओर से हो ताकि जनता के मन में क्या चल रहा है उसे वे बखूबी समझ सकें। झारखंड की आम जनता भी खूब बढ़-चढ़कर सुदेश महतो के साथ जुड़ रही है। उनकी बातों को सुन रही है और अपने गिले-शिकवे उनके समक्ष रख रही है।

उदय कुमार चौहान

स्वराज स्वाभिमान यात्रा का दूसरा चरण पूरा कर रांची लौटने के बाद आजसू प्रमुख ने कहा कि अब गांव और आम आदमी चुप नहीं बैठेगा। सत्ता, सियासत और सिस्टम से गांव भी आंखें मिला कर हक और अधिकार पर बात करेगी। स्वराज स्वाभिमान यात्रा आम लोगों के बीच आवाज बनकर उभरने लगी है। स्वाभिमान यात्रा इस लकीर की सच लोगों को बताते हुए आगे बढ़ रही है। यात्रा के जरिए जिन विषयों को उठाया जा रहा है वह लोगों में विश्वास बढ़ा रहा है। और बोलने का साहस भी। यही वजह है कि इसके मायने निकाले जाने लगे हैं।

27 अक्टूबर को उन्होंने दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत की थी जो दो नवंबर को पूरी की गई। दूसरे चरण में वे खरसांवा, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, सरायकेला, इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 134 गांवों से गुजरे और 92 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस दौरान 56 जगहों पर सभा और चैपाल में साझा संवाद किया।

यात्रा और चैपाल के अनुभवों के बारे में सुदेश कहते हैं कि झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों, मानदेय पर सालों से खट रहे संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, स्वंय सहायता समूह, गांवों- कस्बों के खिलाड़ी, युवा, स्कूली बच्चे, जमीन ले जुड़े स्थानीय कलाकार, बुद्धिजीवी, गांव के प्रतिष्ठत पर्वार इन तमाम वर्ग के पास विचार हैं , सोच हैं , लेकिन कभी उन्हें सुना नहीं गया और सुना भी गया तो शासन, राजनीति , वोट के हिसाब से। यात्रा के दौरान इन वर्ग के साथ सुदेश की बातचीत का सिलसिला जारी है, और यह झारखंड में बदलाव लाएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है।

> **"सुदेश कहते हैं, वे राज्य के पांच हजार गांवों में जाएंगे और लोगों के मन मिजाज पढ़ने समझने के साथ अपनी बात रखने का काम करेंगे।"**

सुदेश कहते हैं कि बड़ी तादाद में आम लोगों की भागीदारी इसके संकेत हैं कि गोलबंदी का दायरा बढ़ने लगा है। लोग चाहते हैं कि गांव, पंचायत के फैसले और समस्याओं पर सरकार और उसके तंत्र के अलावा वोट लेकर चुनाव जीतने वालों से खुलकर बातें की जा सके। वे पूछना भी चाहते हैं कि क्या उनके हिस्से में सिर्फ वोट देने का अधिकार है, लेकिन सरकारी तंत्र और राजनीति ने प्रत्यक्ष- परोक्ष तौर पर दूरियां और हैसियत की लकीर इस तरीके ले खींच रखी है कि आम आदमी उसे लांघने की हिमाकत नहीं करता। सुदेश महतो ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि यात्रा का मकसद बिल्कुल साफ है लोगों की ताकत बनना और झारखंडी विचारधारा को स्थापित करते हुए जनता के विषयों और सवालों के समाधान के लिए रास्ते निकालना। सत्ता के विकेंद्रीकरण को हकीकत में बदलना। वे राज्य के पांच हजार गांवों में जाएंगे और लोगों के मन मिजाज पढ़ने समझने के साथ अपनी बात रखने का काम करेंगे।

खरसांवा से शुरू हुई संवाद की शुरुआत

खरसांवा शहीद स्थल से स्वराज स्वाभिमान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए गांवों के चौपाल में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि गांव में अस्सी साल की वृद्धा पेंशन के लिए आंसू बहा रही है और शासन-सिस्टम इससे बेखबर है। दरअसल गांव का सच और आखिरी पायदान पर छूटे आम आदमी का दर्द आमने-सामने बैठकर ही जाना जा सकता है। लेकिन सरकार, सियासत और साहब के लिए यह प्राथमिकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि स्वराज स्वाभिमान यात्रा के जरिए यही मुहिम छेड़ी गई है कि गांव और आम आदमी की आवाज सत्ता सियासत को डराए। उनके काम क्या हैं इसके ओर आगाह कराए। सबसे पहले वे अरवा गांव गये। वहां बड़ी तादाद में महिलाएं जुटी थी। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की सुनी। फिर अपनी कही। इसी दौरान उन्होंने कहा कि रास्ते में एक अस्सी साल की बुजुर्ग महिला से मुलाकात हुई, जिसे पेंशन का इंतजार है। यह बानगी भर है। कोई एक अदद आवास के लिए सरकार की ओर ताक रहा है। गांव का गांव पानी, बिजली, शौचालय की समस्या में उलझा है। यह हालत इसलिए है कि गांव का संवाद निति निर्धारकों तक नहीं पहुंचती। राजधानी और सचिवालय में बैठकर पूरे राज्य की तस्वीर नहीं देखा जा सकती।

उन्होंने कहा कि एकतरफा फैसला और एकतरफा संवाद परिपाटी बन गई है। इस परिपाटी को बदलने की आवाज भी गांव से उठनी चाहिए। ग्रामीणों से साझा संवाद में उन्होंने कहा कि बिना पैसे का आम आदमी कोई काम नहीं करा सकता। अरवा में एक महिला ने पानी और शौचालय की पीड़ा बताई, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज बनने के लिए ही निकले हैं। गरीब की आवाज धीमी होती है। इसलिए वह सरकार तक नहीं पहुंचती। लेकिन स्वराज स्वाभिमान यात्रा के जरिए गरीबों की इस आवाज को जोरदार बनाने की मुहिम छेड़ी है। लोगों का साथ इसे जन आंदोलन बनायेगा।

> सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, पर गांव के हालात नहीं बदलते। ये रिवाज खत्म करना होगा।

उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बने 18 साल हुए। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था भी लागू हो गई, लेकिन स्वराज और स्वाभिमान के सवाल इस व्यवस्था में गौण होते चले गए।

डोरो गांव में लोगों की बात सुनने के बाद आजसू नेता ने कहा कि सरकार का मतलब पब्लिक होता है इसलिए कि सरकार गठन के वास्ते यही पब्लिक वोट देती है, लेकिन यहां राजनेता के साथ बीडीओ और थानेदार, सरकार बने बैठे हैं। अलबत्ता सरकारें बदलती है, नेता बदलते हैं, पर गांव के हालात नहीं बदलते। ये रिवाज खत्म करना होगा। अब सरकार का हाल चौपाल बताएगा। इसी गांव के एक स्कूली छात्र उत्तम महतो ने बताया कि स्कूल में तीन घंटी ही पढ़ाई होती है। गणित, अंग्रेजी के शिक्षक हैं ही नहीं। उत्तम की बात सुनकर सुदेश ने पहले उसकी पीठ थपाथपाई और कहा ये आवाज सिस्टम तक पहुंचे। सुदेश ने कहा कि ले जहां भी जा रहे हैं लोगों की चिंता इसी बात पर है कि स्कूल में टीचर का टोटा है। तब सरकार को यह जानना चाहिये कि सिर्फ भवन का मतलब स्कूल नहीं होता। बड़ी तादाद में बच्चे अगर सात घंटी की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो इस अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है?

अरवा, डोगो के अलावा सेरेंग्दा, तोड़ामडीह में भी उन्होंने साझा संवाद किया जबकि इचाहातु, पुनिदिरी, दामदिरी, में पदयात्रा की। मारंगहातू गांव में रात्रि चैपाल लगाया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे।

गोइलकेरा में भरी हुंकार

झारखंड के सियासत में कोल्हान का इलाका कई मायने में खास है। सबसे पहली बात तो ये कि इस क्षेत्र में समीकरण के हिसाब से आजसू को कुर्मी वोटों को अगर अपने पाले में कर लेता है तो इसका सीधा फायदा उसे आगामी चुनाव में मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह इस इलाके में सियासी जमीन मजबूत करने का मतलब है बीजेपी के जमीन को खिसकाना, जो कहीं न कहीं आजसू रणनीतिक स्तर पर जरूर करना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए ही सुदेश महतो ने दूसरे चरण की यात्रा में कोल्हान पर फोकस किया। वहां के मुद्दों को तरीके से उठाया, आम आवाम के साथ सीधा संवाद स्थापित किया।

इसी कड़ी में सुदेश महतो ने लोगों से स्वभाविक तौर पर जुड़ने की कोशिश की और वे सफल होते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कोल्हान के गोइलकेरा में पार्टी की उलगुलान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र वीरों और आंदोलनकारियों की धरती रही है। यहां के सपूतों ने कई कुर्बानी दी है। लेकिन इस धरती की पीड़ा है कि अलग राज्य हासिल होने के बाद भी उन वीरों के सपने टूटते रहे हैं। इन हालात को बदलने के लिए उसूलों की लड़ाई जरूरी है। इस लड़ाई का आगाज करने के लिए वे निकले हैं। साथ देने के लिए लोग आगे बढ़ें ताकि यह आगाज अंजाम तक जाए।

सुदेश ने कहा कि उलगुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के प्रति झारखंडियों के दिलों में अथाह प्रेम और स्नेह का यह भी पहचान है कि अब भी लोग अपने बच्चों का नाम गर्व के साथ बिरसा मुंडा रखते हैं। तब ये आवाज आपके बीच से उठनी ही चाहिए कि भगवान बिरसा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज के लिए उलगुलान किया था, इस बेबसी और पीड़ा के लिए नहीं। उसी अबुशा दिशुम और अबुआ राज को स्थापित करने के लिए हमने स्वराज स्वाभिमान यात्रा की मुहिम छेड़ी है।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

सुदेश कहते हैं कि सत्ता में आम आदमी की हिस्सेदारी और झारखंडी विचारधारा को स्थापित करने के लिए लोगों को गोलबंद होना और आवाज को असरदार बनाना जरूरी है। झारखंडी जनमानस के अनुरूप एक नई लड़ाई गांव- गांव से शुरू हो।

उन्होंने कहा कि इस इलाके का जल जंगल, और जमीन से जन्म-जन्म का रिश्ता रहा है। सारंडा की धरती प्रचुर खनिज संपदा और वन संपदा से परिपूर्ण है। लेकिन इस दर्द को महसूस करने की जरूरत है कि जिनकी धरती लोहा, सोना उलगती है वहां के लोग एक अदद छत, रोजी रोजगार और बुनियादी सुविधा के लिए तरसते हैं।

मजदूरी करती मां की कातर निगाहें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच कर सिहर जाती हैं। तब ये पूछा जा सकता है कि इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। आम आदमी सरकार बनाने की खतिर विधायक, सांसद चुन सकता है, तो जनता के नुमाइंदों से यह गारंटी भी भी लेनी पड़ेगी कि सरकारें जनता के मत से चलेगी, साहबों और सियासदानों के मन से नहीं। राजनीति करने वालों का मकसद भी जनता के बीच से ही बदला जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना हो गया है।

सुदेश कहते हैं कि सत्ता में आम आदमी की हिस्सेदारी और झारखंडी विचारधारा को स्थापित करने के लिए लोगों को गोलबंद होना और आवाज को असरदार बनाना जरूरी है। वे लोगों से संवाद करते हुए कहते हैं कि झारखंडी जनमानस के अनुरूप एक नई लड़ाई गांव- गांव से शुरू हो। उन्हें जानकारी मिली है कि इस इलाके में लोहा का कारखाना बैठाने की कवायद हो रही है। लोगों की जमीन ली जाएगी। लेकिन जमीन देने वाले इसके लिए एकजुट रहें कि अगर जमीन ली जाएगी, तो उन्हें कारखाने का हिस्सेदार भी बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, पेंशन, राशन की समस्या ने झारखंड की ताकत और विचारधारा को कमजोर बनाया है। स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं। लाखों बच्चों के भविष्य से खिललाड़ करने के कौन लोग जिम्मेदार हैं यह भी तय करने की जरूरत है। वे अपनी यात्रा के साथ जहां भी जा रहे हैं लोगों के बीच आम धारणा है कि लोकसेवक दाता बन गये हैं और सत्ता के मालिक याचक। यह रिवाज बदलने के लिए एक निर्णायक लड़ाई की जरूरत है। सुदेश महतो कहते हैं कि स्वराज स्वाभिमान यात्रा पूरे राज्य में एक अलग किस्म का वातावरण तैयार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले चरण की यात्रा ने आम लोगों के बीच परिवर्तन की उम्मीदें जगाई है। झारखंडी विचारधारा तथा जमीनी विषयों पर बोलने की ताकत दी है। इस यात्रा का मकसद यही है कि आम आदमी की आवाज और सवाल सियासत और सत्ता को सुनने-सुलझाने के लिए बाध्य करे।

सुदेश महतो ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर दो अक्तूबर से स्वराज स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत मांडू से की थी। पहले चरण में दस दिनों की यात्रा के दौरान मांडू, गोमिया, बेरमो, डुमरी, सिंदरी में सौ जगह चैपाल लगाकर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ हाशिये पर छोड़े जाते रहे आम आदमी के साथ सीधा संवाद किया गया था।

बीजेपी को खदेड़ने के लिये यहां भी संघर्ष यात्रा

सूबे में सियासी यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए कमर कस चुकी हैं, हालांकि सबसे पहले इसकी शुरुआत झामुमो ने ही की है। कोल्हान में अपने पहले चरण की यात्रा पूरी करने के बाद हेमंत सोरेन ने खूंटी से संघर्ष यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस सिलसिले में वे खूंटी के उलिहातु गांव पहुंचे और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उलिहातु भगवान बिरसा मुंडा का गांव है।

हेमंत सोरेन ने उलिहातु से रघुवर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और उसे जन विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार जल, जंगल और जमीन को लोगों से छीन कर उद्योगपतियों को देना चाहती है।

हेमंत सोरेन ने सीएनटी-एसपीटी के मुद्दे पर भी वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। रघुवर सरकार को आदिवासी मूलवासी विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार जल, जंगल और जमीन को लोगों से छीन कर उद्योगपतियों को देना चाहती है। जिस तरह से अंग्रजों से हमारे पूर्वजों ने लोहा लेकर उन्हें खदेड़ दिया, उसी तरह आज समय आ गया है कि बीजेपी को आगामी चुनाव में खदेड़ने के लिये और राज्य को बचाने के लिये हमें संघर्ष यात्रा में निकलना पड़ा है।

झामुमो का झारखंड संघर्ष यात्रा का द्वितीय चरण सिसई के थाना मैदान में आयोजित जनसभा के साथ समापन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि संघर्ष यात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के जन्म भूमि खूंटी से की गई थी। यह द्वितीय चरण का आखिरी पड़ाव है। इसके माध्यम से वर्तमान सरकार के अराजक नीति को आवाम तक पहुंचाने आए हैं। केन्द्र व राज्य सरकार ने झारखंड के आवाम के सीने में खंजर भोंक रही है। आज झामुमो सामंतवाद शासन के सामने खड़ा है। झारखंड की धरती वीरों की जन्म भूमि है। लेकिन सरकार ने हमारे जमीन पूंजीपतियों को देने के कानून बना दिया। हेमंत ने कहा कि हमारे खेती के जमीन पर डोभा बनवा दिए गए, जहां आदमी के साथ पशु डूब रहा है। पीने को पानी नहीं है। घर-घर शौचालय बनवा दी गई। पानी के बिना लोग शौचालय का उपयोग नहीं करते। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शराब दुकान खोले जा रहे हैं। पारा शिक्षक को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। शराब बेचने वालों को भरपूर वेतन दिया जा रहा है। राज्य के लोग भूखे मर रहे हैं। विधायकों को खरीद कर रघुवर सरकार ने सत्ता हथिया ली। शहीद अलबर्ट एक्का के परिवार को अपमानित किया गया। रघुवर सरकार की अंतिम सांस चल रही है।

हेमंत ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो शहीदों के गांव में शहीद स्थल बनेगा। यदि सरकार नहीं बनी तो जेएमएम के फंड से ये काम करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जात-पात धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। रघुवर दास छत्तीसगढ से मजदूरी करने आए थे, लेकिन शासन करने लगे। उन्होंने कहा कि सिसई के विधायक स्पीकर हैं और आदिवासी मूलवासी विरोधी नीति को पास करा रहे हैं। हमारे जमीन पर कारखाना खुल रहा है, चेक डेम बन रहे हैं। पूर्वजों ने जल, जंगल और जमीन को हमारे नाम किया है लेकिन सरकार यहां खनिज सम्पदा को लूटने का कानून बना रही है।

जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के झारखंड संघर्ष यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने छह दिनों के अंदर 870 किलोमीटर की यात्रा तय की। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में चलाये गये इस अभियान में पार्टी 10 लाख लोगों तक पहुंची। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलिहातू से शुरू संघर्ष यात्रा दो नवंबर को गुमला में संपन्न हुई। अपने इस यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन ने 23 सभाओं को संबोधित किया, तीन रात्रि चौपाल लगायी। साथ ही पांच संवाद कार्यक्रम के तहत युवाओं से रू-ब-रू हुए। संघर्ष यात्रा के दौरान झामुमो ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला।

अब तीसरे चरण की यात्रा की तैयारी चल रही है। छठ पर्व के बाद पार्टी की ओर से तीसरे चरण की संघर्ष यात्रा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर कार्यक्रम तय किया जा रहा है। तीसरे चरण में पलामू प्रमंडल का चयन करने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी की ओर से पांचों प्रमंडल में संघर्ष यात्रा चलायी जा रही है।

@Rajneeti_Guru | @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

रघुवर दास कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र

आजसू प्रमुख सुदेश महतो और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भले ही झारखंड में स्वराज स्वाभिमान यात्रा और संघर्ष यात्रा के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हों लेकिन बीजेपी इन दोनों दलों से कई मायनों में काफी आगे चल रही है। कहा जा सकता है कि पार्टी बहुत पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने काफी पहले ही प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कुछ टास्क दे दिए थे, जिसको पार्टी ने पूरा करने का काम कर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के प्रभारी अमित शाह द्वारा दिए गए टास्क की लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं।

इन सब के बीच आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है इसे देखते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारी रेस हो गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा प्रमंडलीय सम्मेलन के बाद अब विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास स्वयं सम्मेलन की कमान संभालेंगे। छठ महापर्व के बाद इन सम्मेलनों का सिलसिला शुरू होगा, जो अगले 3 माह तक जारी रहेग। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मानें तो पार्टी की कोशिश होगी कि 1 दिन में एक से अधिक विधानसभा को कवर किया जाए, वहीं सम्मेलन के दौरान बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री सीधे मुखातिब होंगे और उन्हें टिप्स देंगे, इसके साथ ही बूथ स्तरीय रिपोर्ट भी तलब की जाएगी।

बीजेपी ने बूथ जीतो, चुनाव जीतो के नारे के साथ 19 तरह के टास्क बूथ स्तर पर तय किए हैं।

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का सारा फोकस बूथ पर है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ जीतो, चुनाव जीतो के नारे के साथ 19 तरह के टास्क बूथ स्तर पर तय किए हैं, इन पर अमल की प्रक्रिया कागजों पर काफी हद तक पूरी हो चुकी है और अब विधानसभावार सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश बीजेपी इन टास्क की जमीनी पड़ताल भी करेगी।

इन सम्मेलनों के माध्यम से सत्ता और संगठन के बीच के समन्वय की कवायद भी निचले स्तर पर की जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार के स्तर से आम जनता विशेषकर गरीब, आदिवासी, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्योरा भी मुहैया कराया जाएगा।

बीजेपी की कोशिश है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की रघुवर दास सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों को हर हाल में आम जनता के सामने रखा जाय, उन्हें उसकी जानकारी दी जाय, इसके साथ ही उन्हें उन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाने के प्रति जागरुक भी किया जाए। प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि सरकार ने जिस प्रकार हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं उससे सत्ता में वापसी में आसानी होगी, जरुरत है कि सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को सही तरीके से जनता के समक्ष रखा जाय।

खाकी और खादी की जान है ये सियासी अफीम है...

खूंटी-चतरा में अफीम से तय होती है सियासत

प्रेमकिशोर

सफेदपोश और माफिया गठजोड़ का ही उत्पाद है अफीम जो उगता तो खूंटी और चतरा के खेतों में है लेकिन इससे जेबें भरती हैं खाकी और खादी की।

ये सियासी अफीम है जो राजधानी रांची से महज 30 किमी की दूरी पर खूंटी में और उससे आगे चतरा में लहलहा रही है। इस अफीम ने सियासत की कई नस्लों को खाद-पानी दिया है। राज्य सरकार की मशीनरी लाख इस फसल को उजाड़ने के दावे करे लेकिन आज का सच तो यही है कि खाकी और खादी की मिली-भगत से बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है। वैसे तो खूंटी में अफीम की खेती पिछले कई दशकों से हो रही है। लेकिन इस साल पिछले साल के मुकाबले बड़े पैमाने पर इसकी खेती शुरू की गई है। इस इलाके में अफीम की खेती को कहीं न कहीं नक्सलियों या सफेदपोश अपराधियों का भी संरक्षण प्राप्त है।

ऐसे में हमने कई गांवों का रुख किया ताकि जमीन पर इसकी सच्चाई देखी जा सके। वहां हमें कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। गांव के कई नौजवान हमसे नाम नहीं छापने की बात करते हैं और बताते हैं कि अफीम की फसल की निगरानी से लेकर पुलिस प्रशासन को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी नक्सली गांव वाले को ही सौंप देते हैं। वहीं नक्सली किसानों को मोटी रकम का प्रलोभन देकर इसकी खेती करवाते हैं। किसान भी कम लागत में अधिक मुनाफा को देखते हुए इसकी खेती को राजी हो जाते हैं।

गांव की सीमा पर अफीम माफिया पत्थर पर संविधान की पांचवीं अनुसूची को अंकित कर अनुसूचित क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को बगैर ग्रामसभा के आदेश के गांव में प्रवेश करने से रोकने की बातों को लिख दिया था।

यही समय है जब तैयारी आखिरी चरण में है। अफीम की खेती सितंबर से अक्टूबर के बीच प्रारंभ हो जाती है और मार्च से अप्रैल तक अफीम तैयार हो जाता है। खूंटी में अफीम की खेती सासंगबेड़ा, साके, रोकाब, कटोई, मुचिया, कसमर, लोंगा, पडासू, हडदलामा गांव और जिले के दक्षिणी अड़की क्षेत्र में होती है।

इस इलाके के जानकार बताते हैं कि अफीम माफिया ऐसी जगहों पर ही खेती करते हैं, जहां पुलिस नहीं जाती है। बीते साल यहां पर करीब 1600 एकड़ में पोस्ते की खेती हुई थी। पुलिस ने कई जगहों पर पोस्ते की फसल को नष्ट किया था। साथ ही कई अफीम माफिया को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन फिर भी इस इलाके में अफीम की खेती हो रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक जिले में पुलिस ने 84 किलो अफीम जब्त की है और इसके साथ ही 30 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि अफीम की खेती पत्थलगड़ी वाले गावों में सबसे अधिक होती है।

दरअसल गांव की सीमा पर अफीम माफिया पत्थर पर संविधान की पांचवीं अनुसूची को अंकित कर अनुसूचित क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को बगैर ग्रामसभा के आदेश के गांव में प्रवेश करने से रोकने की बातों को लिख दिया था। इस लफड़े से बचने के लिए पुलिस गांव के अंदर घुसने से परहेज करती रही है। एक दो बार पुलिस ने किसी अपराधी के गांव में घुसने का प्रयास भी किया था, लेकिन पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घंटों बंधक बनाकर रखा । अड़की के कुरुंगा में पिछले दिनों केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान छापेमारी करने को घुसे थे। ग्रामीणों ने उस टीम को भी कई घंटों तक जबरन रोक कर रखा था। खूंटी के डीसी सूरज कुमार और एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा को जवानों को छुड़ाने के लिए कुरुंगा जाना पड़ा था। इतना ही नहीं डीसी और एसपी को ग्रामीणों को अपने हाथ से माफीनामा लिखकर देना पड़ा था।

इसके बाद जाकर ग्रामीणों ने जवानों को छोडा था। इसके अलावा एक दो बार ओर भी एस तरह की घटना खूंटी के अफीम खेती एरिया में हो चुकी है। ग्रामीणों की फजीहत से बचने के लिए पुलिस पत्थलगड़ी वाले गांव में जाने से परहेज करती थी।

इससे अफीम तस्करों का मनोबल बढता गया। खूंटी में बाहर से अफीम तस्कर आराम से आने और अफीम की खेप ले जाने लगे। अफीम की खेती को सुरक्षा देने के लिए अफीम माफिया लगातार सभी गावों में ग्रामीणों के साथ मिलकर पत्थलगड़ी करने लगे। पत्थलगड़ी को रोकने के लिए पुलिस भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। लेकिन इसी क्रम में पत्थलगड़ी आन्दोलन से जुड़े कुछ नेता और पीएलएफआइ के कुछ उग्रवादियों ने कोचांग में पांच आदिवासी युवतियों के साथ बर्बर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना से पुलिस को पत्थलगड़ी नेताओं को घेरने का बेहतर मौका मिल गया।

माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके आगे किसान किसी की नहीं सुन रहे। पत्थलगड़ी वाले गांवों में ग्रामीणों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पत्थलगड़ी वाले गांवों में घुसकर छापेमारी शुरू कर दिया। इसी क्रम में पुलिस ओर पत्थलगड़ी समर्थकों के बीच अनीगडा में पत्थलगड़ी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई।

पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पत्थलगड़ी समर्थकों ने सांसद कडिया मुंडा के अनीगड़ा स्थित आवास से उनके तीन सुरक्षा गार्ड को असलहा समेत अगवा कर लिया।

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन और रेस में आ गया। यही टर्निंग पॉइंट था, जहां पुलिस स्थायी तौर पर अफीम की खेती को नष्ट कर इलाके को अफीम के कलंक से बचा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

नवंबर का महीना है और अधिकांश ग्रामीण इलाकों में पोस्ते की फसल एक बार फिर लग चुकी है। पत्थलगड़ी वाले गांवों में ग्रामीणों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है लेकिन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके आगे किसान किसी की नहीं सुन रहे। पत्थलगड़ी वाले गांवों में मुंडारी भाषा में पोस्टर चिपका कर ग्रामीणों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जहां ये पोस्टर साटे गए हैं, उसी के अगल -बगल में पोस्ते के पौधे को पानी दिया जा रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफीम की खेती करने वालों को सफेदपोश और पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है। चुनाव का समय आने वाला है। इस धंधे में शामिल नेता अफीम से होने वाली कमाई को चुनाव में झोंकेंगे।

पत्थलगड़ी के कई नेता मीडिया के सामने खुलकर बताते हैं कि कैसे रसूखदार लोग अफीम की खेती को संरक्षण दे रहे हैं। ये लोग तो स्थानीय विधायक ओर सांसद के आदमी पर अफीम की खेती करवाने का भी आरोप लगाते हैं।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

लोकसभा चुनाव 5-6 महीने बाद होने हैं, ऐसे में पलामू में सियासी सूरत कैसी होगी, सांसद बीडी राम को लेकर पलामू के सियासी गलियारे में क्या चर्चा हो रही है। उनके कार्यकाल की उपलब्धियों और उनके आम आवाम के साथ संबंधों की हमने पड़ताल की। पलामू के कुछ राजनीतिक हस्तियों से बातचीत भी हमारे संवाददाता ने की। आइये देखते हैं क्या कहता है पलामू !

आम लोगों से सांसद को कोई लेना-देना नहीं- मनोज भुइयां

प्रभु दयाल तिवारी

वर्तमान सांसद के परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं पार्टी उन्हें टिकट देगी !

देखिए, सांसद बी. डी. राम को पार्टी टिकट देगी या नहीं ये तो उनकी पार्टी ही तय करेगी, इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आज हर दल अपने तरीके से अपने उम्मीदवार का असेसमेंट करा रहा है। अब इनका क्या रिपोर्ट जा रहा है और पार्टी इनके साथ क्या करेगी, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हां, जहां तक इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो लोग तो इनको क्षेत्र में जानते तक नहीं हैं। इन्हें तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला था। इसलिए जीत गए थे, लेकिन इनका किसी प्रकार का कोई उपलब्धि नहीं है जिस पर बात की जा सके। आम जनता में तो किसी भी प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं होती है।

आपकी नजर में सांसद ने अपने कितने वायदे पूरे किये !

सांसद ने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है सिर्फ जुमलेबाजी की है, ये सरकार ही जुमलेबाजी की है। इनकी पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक ही काम है कि किसी भी प्रकार से असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। देख लीजिए, अब जब चुनाव का वक्त आया तो अयोध्या मामला को एक बार फिर ये लोग तूल दे रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा बेरोजगारी, कालाधन और भ्रष्टाचार है उस पर बात नहीं करते। जानबूझकर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इनके लिए कोई मुद्दा मायने नहीं रखता आम आदमी से इनको कोई लेना-देना नहीं है।

आम लोगों के दु:ख दर्द में सांसद शामिल होते दिखे क्या !

देखिए, जनता तो एकदम इंतजार कर रही है कि कब चुनाव की घोषणा हो और उसे इनके खिलाफ बटन दबाने का मौका मिले। इसी इंतजार में जनता बेचैन है। लोगों में सांसद के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। वैसे भी मोदी जी के नाम से चुनाव जीते हैं इनका अपना कोई वजूद नहीं है। हमने सांसद को कभी भी आम लोगों के बीच आते-जाते न ही सुना है, और न ही देखा है। आम लोगों से कोई जुड़ाव जैसी बात ही नहीं है।

पार्टी ने टिकट दिया तो जरूर लड़ूंगा चुनाव- शिवधारी राम

लोकतंत्र में जनता मालिक है वह कुछ भी कह सकती है। लेकिन देखा जाय तो क्षेत्र में कुछ काम तो हुआ है। हमलोगों के भी संज्ञान में जनता के माध्यम से जो बातें आती हैं उसे हम अपनी पार्टी के सांसद के समक्ष रखते हैं।

वर्तमान सांसद के परफॉर्मेंस के आधार क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी!

देखिए, सांसद का जो कार्यकाल रहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि ये पार्टी तय करेगी कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है, आगे क्या किया जा सकता है। हमलोग कार्यकर्ता हैं, उसी रूप में काम करते रहे हैं। इसलिए निजी तौर पर मेरा कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं है। जनता और पार्टी चिंता करेगी इस विषय पर कि क्या किया जाना है। हालांकि जनता जरूर कई प्रकार के आरोप लगाती है। जनता मालिक है वह कुछ भी कह सकती है। लेकिन देखा जाय तो कुछ काम तो हुआ है। हमलोगों के भी संज्ञान में जनता के माध्यम से जो बातें आती हैं उसे हम अपनी पार्टी के सांसद के समक्ष रखते हैं। वो इस पर पहल भी करते हैं।

आपकी नजर में सांसद ने अपने कितने वायदे पूरे किये!

सांसद क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, उसको लेकर हमेशा प्रयासरत हैं। हर वायदे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें समय लगता है। जनता की अनेक मांगें रहती हैं उसको पूरा करने के लिए सांसद अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

आम लोगों के दु:ख दर्द में सांसद शामिल होते दिखे क्या!

हमलोगों के पास जो बातें आती हैं तो जरूर सांसद को उससे अवगत कराते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका समाधान हो। जैसे हमलोगों ने बीडी राम से सांसद कोटे की राशि को लेकर सुझाव दिया था कि एनजीओ के माध्यम से काम नहीं करवाएं बल्कि ऐसे कार्य को कार्यकर्ता के द्वारा करवाएं। क्योंकि जनता में इसके प्रति कई प्रकार की नकारात्मक बातें कही जा रही थीं। हमलोग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ऐसी स्थिति को संभालने का प्रयास करते हैं। ताकि पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।

सांसद आम लोगों के बीच जाते हैं उनसे मिलते हैं उनकी समस्याएं भी सुनते हैं।

क्या आपको बीजेपी टिकट देगी तो चुनाव में उतरेंगे!

देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैं पार्टी के प्रमुख दावेदारों में शामिल था और पूरी मजबूती से पलामू में पार्टी के लिए काम कर रहा था। इस बार मैं उससे कहीं ज्यादा ताकत से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं।

इसलिए अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो हर हाल में चुनाव लड़ूंगा।

मैं भी हूं पलामू से टिकट का उम्मीदवार - जवाहर पासवान

वर्तमान सांसद को उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी।

देखिए, सांसद को टिकट देना या नहीं देना ये फैसला शीर्ष का है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी तय करते हैं कि किसे टिकट दिया जाए। जहां तक आज की बात है तो पूरा देश चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी एक फिर पीएम बनें। और इसके लिए जो भी सांसद हो, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो नेतृत्व जरूर उस पर विचार करेगा। जहां तक सांसद बीडी राम के कार्यकाल की बात है, उस पर मैं कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूं लेकिन पार्टी सारी चीजों पर नजर रखी हुई है। और उस पर वह निर्णय करेगी।

आपकी नजर में सांसद ने अपने कितने वायदे पूरे किये!

जहां तक सांसद द्वारा किए गए वायदों की बात है तो उसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन बीजेपी ने जो वायदे किए हैं उस पर तो काम हो रहा है। सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है।

कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं थी जो पूरी नहीं हुई!

देखिए, सांसद ने जो भी घोषणाएं की हैं, और जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सही तरह से तो पब्लिक बताएगी, हमारे पार्टी के सांसद हैं तो उनका आकलन करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं बीजेपी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा यह चाहता हूं कि पार्टी की छवि जनता के बीच सकारात्मक बने, जनता पार्टी से जुड़े।

आम लोगों के दु:ख दर्द में सांसद शामिल होते दिखे क्या!

देखिए, उनका अपना रूटीन है, मेरा अपना रूटीन है, मैं केंद्र द्वारा आयोजित कोई भी कार्यक्रम, जिसमें केंद्र मुझे कोई जिम्मेदारी देती है। तो मैं उस काम को भलिभांति पूरा करने का प्रयास करता हूं। जैसे उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ के चुनाव में मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरा करने की कोशिश करता हूं। उसी प्रकार प्रदेश में या जिला में जो भी कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करता हूं। अगर कोई कार्यक्रम नहीं है, तो अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहता हूं। इसलिए मैं अपनी जबावदेही को समझते हुए उसे पूरा करने के प्रयास में लगा रहता हूं। सांसद क्या कर रहे हैं ये नहीं बता सकते हैं।

पलामू सीट के लिए शिवधारी राम का नाम सामने आ रहा है इस पर आप क्या कहेंगे!

देखिए, एक बात हम आपको बहुत ही स्पष्ट बता रहे हैं, पलामू लोकसभा सीट के लिए अभी 4 नाम सामने आ रहे हैं, पहला तो सीटिंग सांसद बीडी राम हैं उसके बाद दूसरा शिवधारी राम, तीसरा ब्रजमोहन राम और चौथा मेरा नाम है। और इन 4 नामों पर आप विश्लेषण करेंगे तो सीटिंग सांसद को अगर पार्टी टिकट देगी तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उन्हें अगर टिकट नहीं मिलता है तो बाकी बचे तीन नामों में से शिवधारी जी को पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। वे झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ब्रजमोहन राम जी की स्थिति क्या है। जहां तक मेरी बात है तो मैं दिन रात पार्टी के काम में ही लगा रहता हूं। मैं पार्टी के एक सिपाही की तरह काम कर रहा हूं आगे पार्टी को निर्णय करना है। मैंने केंद्रीय नेताओं से भी कहा है कि आपको लगता है कि सीटिंग सांसद को टिकट देने से सीट अगर निकल सकता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

पलायन पलामू की बड़ी समस्या- किशोर पांडेय

वर्तमान सांसद के परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी

ये तो संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है कि किसे टिकट देना है, लेकिन देखा जाय तो इनका कार्यकाल अच्छा रहा है। पब्लिक भले ही इनसे थोड़ा डरती है क्योंकि पुलिस पदाधिकारी रहे हैं लेकिन ये पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं जिसका काम करना है करेंगे और नहीं करना है तो नहीं करेंगे। किसी को उलझाकर नहीं रखते। इसलिए सांसद बीडी राम को टिकट मिलना चाहिए। क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा लगे रहते हैं। काम करते हैं।

अभी एक और नाम आ रहा है शिवधारी राम का तो ऐसे में वर्तमान सांसद के लिए क्या मुश्किलें बढ़ेंगी।

शिवधारी राम जी मृदुभाषी हैं, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। जब बीडी राम और शिवधारी राम में तुलना की जाएगी तो शिवधारी जी धरती पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है। शिवधारी राम का पब्लिक के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। लोग इनके करीब हैं। जनता के बीच इनकी काफी लोकप्रियता है। अभी तो सरकार ने इन्हें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया है। बताया जाता है कि वे मुख्यमंत्री के करीबी हैं। दूसरी बात ये है कि शिवधारी राम जिस जाति से आते हैं, उनकी जनसंख्या पलामू संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक है।

कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं थी जो पूरी नहीं हुई!

देखिए, क्या घोषणा हुई या नहीं हुई ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यहां जो बाहरी भितरी की समस्या है, दूसरे राज्यों के लोगों को झारखंड सरकार द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिलेगा। यह आज विवादस्पद मुद्दा बन गया है। जो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारे राज्य के बच्चे जब बाहर कहीं जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। रोजगार नहीं मिलता। आज भी पलायन की समस्या विकराल है। जब बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को यहां सरकारी नौकरियों में रोजगार मिलता है तो स्थानीय लोग कहां जाएंगे।

सांसद को क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए

देखिए, मुझे लगता है कि सांसद को इस मुद्दे पर मुखरता से बोलना चाहिए क्योंकि वे पलामू के सांसद हैं और यहां के लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने इस निर्णय को निरस्त नहीं किया है तो लोगों को नुकसान तो होगा ही।

आम लोगों के दुःख दर्द में सांसद शामिल होते दिखे क्या!

देखिए, सांसद के साथ समस्या ये है कि स्थानीय मंत्री के साथ इनका संबंध ठीक नहीं है। या कह सकते हैं कि दोनों के बीच आपसी मतभेद है। तो इससे भी क्षेत्र में परेशानी होती है। इसके साथ ही सांसद को ऐसे गांव को गोद लेना चाहिए था जिसका विकास आज तक नहीं हो पाया है। भवनाथपुर, खोरंभा, भंडरिया जैसे इलाके के कई गांव हैं जहां वे गोद ले सकते थे। जिस गांव किशुनपुर को इन्होंने लिया वह पहले से विकसित गांव है।

हालांकि, सांसद जब भी क्षेत्र में रहते हैं घूमते हैं, लेकिन यहां के किसानों की बात कोई नहीं करता। अभी तक सूखाड़ को लेकर घोषणा नहीं हुई है। सिंचाई की सुविधा पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ राजनीति होती रही है।

झारखंड में गूंजेंगे यदुवंशियों के बोल

यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में...

झारखंड के यदुवंशियों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है, आबादी के हिसाब से कुड़मी के बाद नम्बर दो के स्थान पर खड़े यादव समाज के सबसे बड़े आध्यात्मिक नायक और प्रख्यात शिव भक्त बाबा बैजू के नाम पर आज तक देवघर में ना कोई प्रतिमा है ना ही कोई अन्य प्रतीक स्थल।

झारखंड की धरती पर आगामी 18 नवंबर को अखिल भारतीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पहली बार प्रदेश के इतने बड़े सार्वजनिक मंच से यदुवंशियों की सामाजिक उदघोषणा सुनाई देगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए झारखंड प्रदेश यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष बजरंगी यादव और प्रदेश की पूरी टीम ने राज्यभर से सक्रिय यादव समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को रांची बुलाया है। जहां एकजुट यादव समाज की जोरदार आवाज़ सुनाई देगी।

इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए स्वागताध्यक्ष बजरंगी यादव ने बताया कि प्रदेश का यादव समाज अब मुखर है और सत्ता केंद्र को हमारी परेशानी सुननी ही पड़ेगी। यादव समाज कभी भी केवल अपनी बात नहीं करता बल्कि पूरे पिछड़े समाज के हक के लिए मुखर रहता है। अब ज्यादा दिनों तक हमारी बात दबायी नहीं जा सकती।

सचमुच, प्रदेश के यदुवंशियों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है, आबादी के हिसाब से कुड़मी के बाद नम्बर दो के स्थान पर खड़े यादव समाज के सबसे बड़े आध्यात्मिक नायक और प्रख्यात शिव भक्त बाबा बैजू के नाम पर आज तक देवघर में ना कोई प्रतिमा है ना ही कोई अन्य प्रतीक स्थल।

संभव है यादव महासभा की रांची राष्ट्रीय कार्यसमिति के बाद प्रदेश में यादव समाज की निर्णायक ताकत दिखे और सत्ता प्रतिष्ठान को भी यादवों की ताकत का अहसास हो।

जिनके नाम पर बैजनाथ महादेव का नामकरण हुआ। जिनके वंशज आज भी महादेव और महादेवी मंदिरों के बीच गठबंधन का पवित्र धागा बांधते हैं और शिवभक्तों की मनोकामना जिनके माध्यम से पूरी होती है। उनके सम्मान में समाज एक विशाल धर्मशाला के निर्माण पर भी निर्णय ले सकता है, जिसपर राष्ट्रीय कार्यसमिति अपनी मोहर लगायेगी। यह समाज के ऐतिहासिक अतीत को सम्मानित करने की बड़ी कोशिश होगी।

इसके अलावा समाज मंडल कमीशन की संवैधानिक सिफारिशों को झारखंड में तत्काल लागू करने की मांग भी करेगा। पूरे देश में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता है,जबकि झारखंड में पिछड़ों को प्रदेश स्तर पर मात्र 14 फीसदी आरक्षण ही मिलता है, जिला स्तर पर तो स्थिति और भी खराब है। आधा दर्जन से अधिक जिलों में तो पिछड़ों को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता। यादव समाज पिछड़ों के इस संवैधानिक हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है। बजरंगी यादव कहते हैं कि अभी तो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही पिछड़े समाज से हैं। अभी भी अगर पिछड़ों को उनका वाज़िब हक नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा! राष्ट्रीय कार्यसमिति में यह मांग जोरदार ढंग से उठेगी। पिछड़े कोई भीख नहीं मांग रहे,किसी और की हकमारी नहीं कर रहे केवल अपना संवैधानिक हक मांग रहे हैं। हमें और वंचित मत रखो, पिछड़े नौजवानों के अवसर मत छीनो।

अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के झारखंड में होने का सांकेतिक महत्व है। प्रदेश का यादव समाज पिछड़े वर्ग को लीड करता है। आधा दर्जन से अधिक विधान सभा और 2 लोक सभा सीटों पर निर्णायक असर रखने वाले यादव समाज के प्रभावशाली लोग जुटेंगे तो आगे की सामाजिक और सियासी राह को लेकर विचार मंथन होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर महासभा सैनिकों के लिए अहीर बटालियन की मांग लंबे समय से कर रहा है। ऐसे कई और डिमांड्स हैं। जिसे राष्ट्रीय कार्यसमिति में ताकत से रखा जायेगा।

संभव है यादव महासभा की रांची राष्ट्रीय कार्यसमिति के बाद प्रदेश में यादव समाज की निर्णायक ताकत दिखे और सत्ता प्रतिष्ठान को भी यादवों की ताकत का अहसास हो।

सरकार से नाराज हैं खूंटी के लोग

बह रही बदलाव की बयार

■ प्रेमकिशोर

आदिवासी बहुल खूंटी विधानसभा क्षेत्र में मुंडा की जनसंख्या अधिक है, किसी भी पार्टी प्रत्याशी की जीत और हार मुंडा वोटर ही तय करते हैं।

झारखंड में खूंटी का विशेष स्थान रहा है, यह भगवान बिरसा मुंडा की मातृभूमि और कर्मभूमि है, वहीं, कद्दावर नेता जयपाल सिंह, झारखंड आंदोलन से जुड़े एनइ होरो, खूंटी के गांधी कहे जानेवाले टी मुची राय मुंडा और कड़िया मुंडा जैसे दिग्गज नेताओं ने इस इलाके को एक अलग पहचान दिलायी है। इन सब के बावजूद आज यह क्षेत्र अपराध के लिए जाना जाता है। इस जिले में भाकपा माओवादियों व पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआइ) की तूती बोलती है। जिले में बेरोजगारी चरम पर है, पलायन यहां की आम समस्या है। रोजगार सृजन के लिए इस जिले में कुछ भी नहीं किया गया। यही वजह है कि पूरा जिला नक्सलवाद की चपेट में है।

इस इलाके के जानकार कहते हैं कि पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाला खूंटी 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर नया जिला बना था। यहां के कई नेता केंद्र व राज्य में मंत्री रहे, लेकिन किसी ने विकास की दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि जिले में न तो कोई उद्योग खुला और न ही किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हुई। हां, घोषणाओं व शिलान्यास की कमी यहां कभी नहीं रही। नेताओं व जन प्रतिनिधियों ने एजुकेशनल हब, कृषि विज्ञान केंद्र व पर्यटन स्थलों के विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं की और शिलान्यास किया। ये कर्म कांड हुए वर्ष बीत गये, पर किसी योजना पर काम शुरू नहीं हुआ। एजुकेशन हब के नाम पर जिन रैयतों की जमीन का अधिग्रहण हुआ, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है।

राजनीतिक जानकार बताते हैं कि आदिवासी बहुल खूंटी विधानसभा क्षेत्र में मुंडा की जनसंख्या अधिक है, किसी भी पार्टी प्रत्याशी की जीत और हार मुंडा वोटर ही तय करते हैं। इसके बाद यहां पर सदान का वोटर हैं, उसमें पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक है।

कुल मिलाकर देखा जाय तो पिछड़ी जातियां और मुंडा वोटर ही खूंटी का विधायक तय करते हैं। बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा करीब 40- 45 हजार मतों से चुनाव जीते थे। झामुमो के जीदन होरो दूसरे और कांग्रेस की पुष्पा सोरेन तीसरे स्थान पर रही थीं।

खूंटी के बिनसाय मुंडा, मार्शल बरला कहते हैं कि सरकारें आईं और गईं लेकिन खूंटी की किस्मत नहीं बदली। उनका मानना है कि आजादी के बाद भी उनकी गांव की दुर्दशा देखने कोई नहीं आया। लोग जानवरों से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। गांव में आज तक तालाब-कुआं नहीं बन पाया। पीने के पानी के लिए भी आज भी नदी, झरनों का ही सहारा है।

मर्शल बरला कहते हैं कि भाजपा का खूंटी विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से शासन रहा है, इसके बावजूद क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, चारो ओर जहां भी चले जाइए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि खूंटी विधान सभा में सदानों का वोट ही कोई भी पार्टी की प्रत्याशी की जीत हार तय करती है। यहां पर 25 से अधिक गांव सदानों का है, खूंटी विधानसभा में सदान वोटरों की संख्या 4ड फीसदी और आदिवासी 60 फीसदी हैं। सूबे का सबसे पिछड़ा इलाका होने के बावजूद मतदान करने में यहां के वोटर काफी आगे रहते हैं।

खूंटी शहर के तोरपा रोड के रहने वाले प्रेम कुमार की मानें तो इस बार विधान सभा चुनाव में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आरक्षण के कारण योग्य लोग सामने नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा आरक्षण को लेकर जो लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। प्रेम आगे कहते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई करतें पर आरक्षण की बात सोचकर उसमें मन नहीं लगता हैं।

वहीं बाजारटांड़ में रहने वाले सुदेश कुमार जायसवाल, मुकेश महतो, आनंद महतो की मानें तो यहां पर निर्णायक वोटर तेली समाज है। तेली समाज जनसंख्या 35 फीसदी से ज्यादा है। जबकि रिकार्ड में तेली समाज को सामाजिक और आर्थिक तौर पर शून्य कर दिया गया है।

मिश्रा टोली के अनिल मिश्रा कहते हैं कि यहां पर ब्राह्मण समाज की आबादी लगभग 2 हजार है। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को लगभग सभी पार्टियों ने ठगने का काम किया है। सरकार हमलोगों को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं देती है, हम लोग अपनी मेहनत से कमाते और परिवार का गुजारा करते हैं।

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राम कृष्णा चौधरी कहते हैं कि खूंटी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी 60 फीसदी और 40 फीसदी सदान वोटर हैं, उन्होंने कहा कि झारखण्ड नामधारी पार्टी आने के बाद कांग्रेस के वोटों का बिखराव हुआ है, बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता रहा है। राम मंदिर और हिंदू कार्ड का ड्रामा कर वह जनता से वोट लेने में कामयाब हो जाती है। समाज में एक दूसरे को लड़वाने का कार्य भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेता करते हैं। लोग अब इस बात क समझने लगे हैं। इसलिए इस बार चुनाव में लोग भाजपा के झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा पुराना हो गया है। जो देश ओर राज्य का विकास करेगा जनता उसे ही वोट करेगी।

राम कृष्णा चौधरी आगे कहते हैं कि रघुवर सरकार में खूंटी में विकास योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ शिलान्यास हुए हैं। खूंटी में अगर कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा होता है तो स्थिति बदल जाएगी। वैसे देखा जाय तो यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। वो कहते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन भाजपा से अधिक मजबूत है, फिलहाल बीजेपी की प्रदेश में सरकार है और स्थानीय विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ मुंडा सरकार में हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी की स्थिति ठीक है पर ऐसा नहीं है और चुनाव की घंटी बजने के साथ ही वे सभी कांग्रेस की तरफ आ जायेंगे।

विधानसभा चुनाव में 1977 में खुदिया पाहन, जनता पार्टी से 1980 सामू पाहन, इंदिरा कांग्रेस से 1985 में सुशीला केरकेट्टा, कांग्रेस 1990 सुशीला केरकेट्टा, वहीं 1995 सुशीला केरकेट्टा, वहीं 2000 में नीलकंठ सिंह मुंडा, भाजपा, 2005 नीलकंठ सिंह मुंडा, 2009 नीलकंठ सिंह मुंडा जीते।

राम कृष्णा चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस नेत्री सुशीला करकेट्टा तीन टर्म से यहां से विधायक रहीं, उसके पहले सोमा पाहन और स्व. मुचिराय मुंडा 71 से 77 तक विधायक रहे। भविष्य कांग्रेस का है, जनता टकटकी लगाये कांग्रेस की ओर देख रही है। चौधरी कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग जिसके साथ चला जायेगा उसकी जीत हो जायेगी।

वहीं, झाविमो के जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा की मानें तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीट आधी से भी कम हो जायेगी। सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता रघुवर सरकार से नाराज चल रही है। पार्टी को जबरदस्त झटका लगने वाला है। उन्होंने कहा कि पत्थलगड़ी भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था। विकास योजनाओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए पत्थलगड़ी का कार्यक्रम करवाया गया।

दो भाजपा नेता की कलह से पत्थलगड़ी का मामला सामने आया। यह सिर्फ खूंटी और तमाड़ विधानसभा में अधिक हुई है। अफीम की खेती खूंटी और अड़की में होती है। मुंडा बेल्ट में पोस्ता की खेती हो रही है। पुलिस अफीम की खेती करवा रही है। एसआर फंड का दुरूपयोग हो रहा है।

दिलीप मिश्रा कहते हैं कि खूंटी विधानसभा में टिकट उसे ही मिलेगा जिसका पहले हुए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस और झामुमो दावेदारी तो करेंगे लेकिन झाविमो को सीट मिलना चाहिए।

वहीं, आजसू नेता सह झारखण्ड तेली समाज के युवा प्रदेश महासचिव जयकांत कुमार कशयप ने भी सरकार के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली। वो कहते हैं कि खूंटी में इंडियन ऑयल में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया।

यहां किसी तरह की त्रासदी होगी तो जिम्मेदार कौन होगा। इसमें स्थानीय लोग ही मारे जायेंगे। सरकार स्थानीय लोगों को सिर्फ ठगने का कार्य करती है। इतने सालों बाद भी बिरसा कॉलेज को जमीन का नहीं आवंटन हुआ है, जिसे जमीन मिला वहां नॉलेज सिटी नहीं बना। जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी योजना अधर में लटक गई है। रेलवे लाइन का प्रस्ताव भी अधर में लटक गया है।

उधर, झामुमो जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद कहते हैं कि वर्तमान में खूंटी की जनता बदलाव चाहती है, वह आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। पहली बार बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनी, लेकिन सामान्य, आदिवासी, सदान किसी को कोई भी लाभ नहीं मिला। सरना भाइयों का कुछ भाग झामुमो को, तो कुछ भाजपा को सपोर्ट करता है। पर इस बार वह सभी लोगों ने मूड बना लिया है कि वे झामुमो को ही वोट देंगे।

जुबेर अहमद बताते हैं कि इस बार क्षेत्र में कम बारिश होने से खेती नहीं हुई, किसानों को हाल बुरा है, इसके बाद भी सरकार ने खूंटी जिले को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को हराने के लिए काफी हैं।

जुबेर अहमद की मानें तो खूंटी में मुस्लिम वोटरों की संख्या 15 से 20 हजार के करीब है। इस बार मुस्लिम वोटर झामुमो की तरफ जाएंगे। उनकी मानें तो बीजेपी का वोटर व्यापारी वर्ग भी जीएसटी से परेशान है, इसलिए झामुमो के संघर्ष यात्रा के दौरान जनता खुलकर सामने आई। इसका लाभ चुनाव में जरूर झामुमो को मिलेगा। खूंटी विधानसभा में झामुमो प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा।

भाजपा के जिलाध्यक्ष काशीनाथ महतो कहते हैं कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, खूंटी का निरंतर विकास हो रहा है। स्थानीय विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा हमेशा जिले के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। जिले में सड़कों का जाल फैला दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र से जिला मुख्यालय तक आने में अब ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, गांव- गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है। लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

क्या उपेन्द्र कुशवाहा की हैसियत महज़ 2 सीटों की !

NDA सीट शेयरिंग : 17-17 पर JDU-BJP, 4 पर LJP तो 2 पर RSLP !

सिद्धांत के तौर पर राजनीति में वक्त का तकाजा होता है। ऐसे में जो भी फैसले लिये जाते हैं, वे किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही होते हैं। भावनाओं की टोपी तो कई बार पहना दी जाती है। ऐसे में जब एक ही वक्त नीतीश-अमित शाह संयुक्त रूप से प्रेस से मुखातिब थे, तो दूसरी ओर रामविलास पासवान के गढ़ में तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की बंद कमरे में बातचीत चल रही थी।

प्रणव

सिद्धांत के तौर पर राजनीति में वक्त का तकाजा होता है। ऐसे में जो भी फैसले लिये जाते हैं, वे किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही होते हैं। भावनाओं की टोपी तो कई बार पहना दी जाती है। ऐसे में जब एक ही वक्त नीतीश-अमित शाह संयुक्त रूप से प्रेस से मुखातिब हों तो दूसरी ओर रामविलास पासवान के गढ़ में तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की बंद कमरे में बातचीत चल रही थी। आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना खास हो जाता है।

दो पाटन के बीच में साबुत बचना मुश्किल

कहने को तो शाह और नीतीश ने इस पर रजामंदी जता दी कि जदयू-भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेंगे। फिर, पासवान का क्या होगा और कुशवाहा कहां जाएंगे अब। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय- लगभग यही कुछ होना है अब बिहार में। राह तो भाजपा और जदयू की भी आसान नहीं है। क्योंकि, दोनों ही दलों के नेता इस बार बागी होंगे और इस मौके का इंतजार राजद कर ही रहा है।

दावे तो कूटनीति की राजनीति में हमेशा जीत के ही होते हैं, लेकिन मन में तो हार का डर बैठा ही रहता है। यही हाल, भाजपा की भी है और नीतीश की भी।

2015 के विधानसभा चुनाव ने सबकुछ उलट-पुलट कर दिया

दावे तो कूटनीति की राजनीति में हमेशा जीत के ही होते हैं, लेकिन मन में तो हार का डर बैठा ही रहता है। यही हाल, भाजपा की भी है और नीतीश की भी। यह सब कुछ हुआ है 2014 के चुनावों के बाद। बड़े भाई के पाला बदल लेने से भाजपा ने खुल कर खेला। जदयू के कोटे की सीटों को कुछ अपने पास रखा तो कुछ पासवान और कुशवाहा को दे दिया। हालात बदलते ही हैं। अब 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने एनडीए को औकात बता दी। दिल्ली के बाद मोदी-मैजिक की हार बिहार में हुई थी। यह जो दो-तीन दिन का वक्त लिया गया है सीटों की घोषणा करने में, उसका कारण है पासवान और कुशवाहा का मूड भांपना।

पासवान ज्यादा खतरनाक, कुशवाहा कर रहे इंतजार

इसमें ज्यादा खतरनाक पासवान हैं, जो चुपचाप पाला बदलते हैं। बस मुद्दा खोजने की देर रहती है। 2009 की जबरदस्त हार ने पासवान को चिराग की यह सलाह मानने को मजबूर कर दिया था कि इस बार मोदी-मैजिक चलेगा। पर, कुशवाहा संकेत देने की राजनीति कर रहे हैं। कुशवाहा ने यह तो साफ कर दिया है कि वे रहेंगे एनडीए में ही, लेकिन चाहते हैं कि उनको तीन सीटिंग सीटें तो मिले ही।

बड़े भाई के कंधे पर छोटे ने हाथ रख ही दिया आखिरकार

दरअसल, यही वह टर्निंग प्वाइंट था, जिसके कारण आज ये हालात बन गए कि जदयू अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहा। भाजपा अब आंख मिलाकर सौदेबाजी कर रही है। विभाजित बिहार में कुछ पॉकेट ऐसे हैं, जहां दोनों के बीच परदे के पीछे जंग होगी। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में भाजपा अपनी जीती हुई सीटों को गंवाना नहीं चाहेगी। गंगा से उत्तर और कोशी की धारा के आसपास के इलाके में पासवान अपनी चलाना चाहेंगे। गंगा के दक्षिण और आसपास के इलाके में नीतीश किसी को घुसने नहीं देंगे। ऐसे हालात में सीटों के बंटवारे का फार्मूला निकालना बेहद कठिन होने जा रहा है।

जीत का फार्मूला निकालना बेहद कठिन

आकलन के मुताबिक भाजपा और जदयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। चार सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी जा सकती है और कुशवाहा की आरएसएलपी को दो सीटें। जानकारी और संभावनाओं के आधार पर भाजपा उत्तर बिहार में वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज की सीटें नहीं छोड़ना चाहेगी। मुजफ्फरपुर पर भी उसने दावा ठोंक दिया है। नीतीश के मेंटर रहे जार्ज इसी सीट से जीतते रहे थे। बाद में इस पर कैप्टन जय नारायण निषाद लड़े नीतीश की पार्टी की टिकट पर। 2014 में आपसी खींचतान की वजह से नीतीश उनको बदलने के मूड में थे। ऐसे में भाजपा ने उनके बेटे अजय निषाद को टिकट दिया और वे मोदी-मैजिक में जीते भी। यदि भाजपा यह सीट अपने पास रख लेती है तो फिर वह उत्तर पश्चिम बिहार से जदयू को पूरी तरह रिप्लेस कर सकती है। हां, महाराजगंज पर उसे समझौता करना ही होगा। यह सीट नीतीश के पास जाएगी। बदले में जदयू को अपनी परंपरागत वाल्मीकिनगर की सीट भाजपा को सौंपनी पड़ सकती है।

समस्तीपुर और उजियारपुर की सीट पेंच फंसा सकती है। यहां से नीतीश हर हाल में प्रत्याशी उतारना चाहेंगे। पर, उजियारपुर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सांसद हैं। इस इलाके में यादव वोटों की सेंधमारी के लिए राजद की काट वे हो सकते हैं। ऐसे में यदि वह उजियारपुर सीट गंवाती है तो फिर नित्यानंद राय को सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

समाजवाद की जमीन पर नीतीश की नजर

अब इसके बाद देखते हैं कि गंगा के उत्तर और कोशी तट के इलाके को, इसे समाजवाद की जमीन कहा जाता है। यहां क्या हालात हो सकते हैं! यहां जातिवाद जबरदस्त फैक्टर माना जाता है। हाजीपुर तो पासवान की परंपरागत सीट है। बस, 2009 में वे जदयू के रामसुंदर दास से हारे थे। ऐसे में यहां कोई संशय नहीं है। इस इलाके में नीतीश के लिए बड़ी चुनौती होंगे पासवान। वैशाली सीट भी वे चाहेंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी के रामा सिंह यहां से जीते थे।

अब वे उनकी पार्टी में नहीं हैं, तो वे अपने बेटे चिराग को यहां से लड़ा सकते हैं। क्योंकि, जमुई पर जदयू दावा ठोंक रही है। इसके बाद खगड़िया, रोसड़ा, अररिया पर वे दावा ठोंक रहे हैं। इसमें कुछ सीटें भाजपा के पास है। दरअसल, मुंगेर और जमुई पर नीतीश अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। पूर्णिया नीतीश छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि, वे यहां राजद की वजह से जीते थे।

नित्यानंद राय को संतुष्ट रखना बड़ी चुनौती

समस्तीपुर और उजियारपुर की सीट पेंच फंसा सकती है। यहां से नीतीश हर हाल में प्रत्याशी उतारना चाहेंगे। पर, उजियारपुर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सांसद हैं। इस इलाके में यादव वोटों की सेंधमारी के लिए राजद की काट वे हो सकते हैं। ऐसे में यदि वह उजियारपुर सीट गंवाती है तो फिर नित्यानंद राय को सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि, दो उपमुख्यमंत्री बनाने की चर्चा भी तेज है।

यहां नीतीश को कोई चुनौती नहीं दे सकता

गंगा के दक्षिण के जो भी इलाके हैं, उस पर नीतीश के दावे को कोई चुनौती भी नहीं देगा। बाढ़, नालंदा, बेगूसराय तो सेफ है। फिर, नवादा में जाकर पेंच फंस सकता है। यहां से गिरिराज सिंह सांसद हैं। वे हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता हैं, ऐसे में उनको हटाने का रिस्क भाजपा नहीं लेगी। गया में भी नीतीश की दाल नहीं गलेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यदि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से उतारती है तो फिर यह सीट जदयू के पास जा सकती है। क्योंकि, साम्यवाद को समाजवाद ही हरा सकता है। भोला सिंह तो भाकपा से लेकर भाजपा तक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी अपनी जमीन थी, जो पार्टियों के एजेंडे से ऊपर थी।

पेंच फंसने की आशंका सबसे ज्यादा इस इलाके में

अब बात आरा, बक्सर, सासाराम के इलाके की। यदि भागलपुर से शाहनवाज को भाजपा उतारती है तो बक्सर की सीट से अश्विनी चौबे ही लड़ेंगे। ऐसे में आरा और सासाराम की सीट उसे जदयू को देनी पड़ सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर भाजपा औरंगाबाद को अपने ही पास रख बक्सर को जदयू को सौंप सकती है। लेकिन, यहां यह याद करने की बात है कि इस इलाके में भाजपा के लिए जमीन लालमुनि चौबे ने तैयार की थी।

दरभंगा और समस्तीपुर है बेहद खास

मिथिलांचल की ओर देखा जाए तो यहां भाजपा कीर्ति आजाद का टिकट काट सकती है। लेकिन, सीट तो अपने पास ही रखेगी। मधुबनी सेफ है, क्योंकि हुकुमदेव नारायण यादव यहां से भाजपा के सांसद हैं। समस्तीपुर में भाजपा को पासवान से मुकाबला करना होगा। जबकि नीतीश यहां अपना प्रत्याशी चाहेंगे। यह सब जानते हैं कि समस्तीपुर में लोजपा की जीत मोदी-मैजिक के सहारे हुई थी। यह भी याद रखना होगा कि यह इलाका कर्पूरी ठाकुर का है।

पूर्वांचल पर सभी की नजरें

पूर्वांचल की ओर सभी दल अपने लिए एक-दो सीट चाहेंगे। कटिहार को भाजपा अपने पास ही रखेगी। किशनगंज वह जदयू को देना चाहेगी, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटर ही जीत-हार तय करता है। सुपौल, सहरसा के लिए भाजपा, लोजपा और जदयू में जंग होगी। यह इलाका यादव बहुल है। राजद की जमीन मानी जाती है। पर, अन्यों की गोलबंदी उसे परेशान करती है। पेंच तो मधेपुरा पर है।

यह भी यादव बहुल है। इस बार शरद यादव वहां से यदि चुनाव राजद की वैशाखी पर लड़ते हैं तो भाजपा पप्पू यादव को उतार सकती है। पर, सहरसा से सांसद रंजीता रंजन क्या अपने पति का विरोध कर सकेंगी। यदि नीतीश के पास यह सीट जाती है तो वे शायद ही पप्पू को टिकट दें। वैसे मधेपुरा की सीट का एक सांकेतिक महत्व भी है।

कुशवाहा के लिए हालात बेहद मुश्किल

इस तरह के हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जगह क्या बचती है। काराकाट से उनका टिकट नहीं कटेगा। पर, सीतामढ़ी वे गंवाने जा रहे हैं। क्योंकि, उनकी कोई जमीन वहां नहीं है और मोदी-मैजिक के सहारे यह सीट जीती गई थी। जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार अपनी अलग राह चुन चुके हैं। वे नीतीश की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

ऐसे में काफी मुश्किल से कुशवाहा की पार्टी के लिए एक या दो सीट बनती है। वैशाली की सीट पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि, कुशवाहा का यह गृह जिला है। हालांकि, यह भी दूर की बात है। कुशवाहा इस बात को समझते हैं, इसलिए वे विद्रोह पर उतारू हैं। पर, उनको यह समझना होगा कि 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। यदि वे नीतीश से कुछ वोट छीन पाते तो हालात दूसरे होते।

पटना साहिब और मधेपुरा पर भी फंसा है पेंच

पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट तो कटना तय लग रहा है भाजपा से। ऐसे में उसे नए चेहरे की जरुरत होगी। दरभंगा की सीट पर भी यही हालात हैं। रामकृपाल की भी सीट बदली जा सकती है। पर, भाजपा को यहां से किसी दूसरे प्रभावशाली यादव को ही उतारना होगा। बदले हालात में मधेपुरा से रामकृपाल को भाजपा लड़ा सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रंजन यादव वहां नीतीश की पार्टी की टिकट पर जा सकते हैं। पर, शत्रुघ्न के लिए यह खास है कि पटना इलाके में उनके सजातीय कायस्थों की संख्या अधिक है। उनकी नाराजगी झेलना भाजपा नहीं चाहेगी। ऐसे में नितिन नवीन को आगे किया जा सकता है।

इस बार मोदी-मैजिक नहीं, जमीनी हकीकत पर होगी लड़ाई

यह तो तय है कि इसबार कोई मैजिक या लहर नहीं है। ऐसे में जमीनी हकीकत और जातिगत वोट ही उम्मीदवारों की जीत-हार तय करेंगे। ऐसा अनुमान है कि भाजपा की नजर मुकेश सहनी पर भी है। क्योंकि, जातिगत रूप से मल्लाहों-निषादों की संख्या बिहार के उन जिलों में ज्यादा है, जो नदियों के आसपास के हैं। सवर्णों की नाराजगी का जोखिम भी भाजपा को सता रहा है। प्रेम कुमार के अलावा उसके पास कोई बड़ा दलित फेस है नहीं। यही हाल जदयू का भी है। ऐसे में पासवान की अहमियत बढ़ जाती है।

शहादत और सहानुभूति की चाहत

यह गनीमत ही होगी कि भाजपा और जदयू 17-17 के तहत चुनाव लड़ें। पासवान को चार या पांच सीटें दी जा सकती है। उपेंद्र को दो सीटें मिल सकती हैं। जदयू की मेहरबानी रह गई तो तीन भी हो सकती है। आपसी समझ के तहत कुछ उम्मीदवारों की अदला-बदली भी हो सकती है। पर, यह सब इतनी आसानी से नहीं होनेवाला। क्योंकि, चुनाव की पूर्व संध्या पर हर राजनीतिक दल या व्यक्ति सहानुभूति और शहादत की इच्छा रखता है। चाहे वह शख्स उपेंद्र कुशवाहा हो या शत्रुघ्न सिन्हा या फिर कीर्ति आजाद।

नीतीश को यहां पर BJP-LJP से मिलेगी चुनौती

नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीटों की संख्या के साथ-साथ उनको चिह्नित भी कर लिया जाए, ताकि तैयारी के लिए पुख्ता समय मिल सके। कयासों और लंच से पहले जदयू नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बातचीत में जो संकेत दिये हैं, उसके मुताबिक सीटें चिह्नित कर ली गई है। उन पर थोड़ी इधर-उधर के बाद लगभग बात फाइनल स्टेज में है।

नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीटों की संख्या के साथ-साथ उनको चिह्नित भी कर लिया जाए, ताकि तैयारी के लिए पुख्ता समय मिल सके।

इन सीटों पर जदयू की होगी नजर

जदयू ने जिन-सीटों पर अपना दावा ठोंका है, उनमें वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, महाराजगंज, उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय और सासाराम हैं। उसकी नजर काराकाट और वैशाली की सीट पर भी है। इन सीटों पर सीतामढ़ी और काराकाट आरएसएलपी के पास है। वाल्मीकिनगर भाजपा के पास है। सुपौल कांग्रेस के पास है। बेगूसराय, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, उजियारपुर भाजपा के पास है। समस्तीपुर, जमुई लोजपा के पास है।

समस्तीपुर, उजियारपुर और जमुई पर फंसेगा पेंच

भाजपा मुजफ्फरपुर और उजियारपुर की सीट बचाएगी ही। दूसरों पर कुछ राहत जदयू को दे सकती है। सीतामढ़ी से कुशवाहा को हटाने के मूड में है जदयू। यदि कुशवाहा दो सीटों पर मान जाते हैं तो काराकाट की सीट वह छोड़ सकती है और जहानाबाद पर नजर टिकाएगी ही। लोजपा से उसका झगड़ा समस्तीपुर और जमुई को लेकर हो सकता है। जमुई से चिराग पासवान सांसद हैं। हां, पासवान वैशाली पर राहत दे सकते हैं जदयू को।

अब जबकि जदयू-भाजपा और एनडीए के नेता सीटों को चिह्नित करने में जुटे हैं तो इन सीटों पर जदयू की नजर है। इसमें भाजपा को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में असंतुष्टों को बिहार सरकार में जगह दी जा सकती है तो जदयू के असंतुष्टों को शायद केंद्र में।

■ प्रणव

न नीतीश रहे दोस्त न लालू

चौराहे पर कीर्ति-शत्रु की राजनीति

कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे शत्रुघ्न सिन्हा आज चुनावी मंचों से पूरी तरह गायब हैं। कीर्ति झा आजाद की स्थिति तो और भी खराब है। बीजेपी की टीम से उन्हें इस प्रकार आउट किया जाएगा, इसका अंदाजा उनको भी नहीं होगा।

जलती हुई को आग कहते हैं। बुझी को राख और जो राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं- फिल्म विश्वनाथ का यह डॉयलॉग शत्रुघ्न के बेहद चर्चित डॉयलाग्स में से एक है। आजकल यह उनके राजनीतिक जीवन में पूरी तरह चरितार्थ होता हुआ दिखता है। खामोश हैं। कभी-कभी बोलते हैं। आजकल नीतीश कुमार से मिलने भी नहीं जा रहे। लालू-तेजस्वी से भी चुप-चुप से हैं। आखिर क्या सोच रहे हैं शत्रुघ्न। कुछ ऐसा ही हाल क्रिकेटर से राजनेता बने कीर्ति आजाद का है। कांग्रेसी दिग्गज व पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के बेटे हैं। दरभंगा में कम दिल्ली में वक्त ज्यादा देते हैं। उनको भी भाजपा ने शंट कर दिया है। उनकी हालत यह है कि वे किसी के पास नहीं जा रहे। गाहे-बगाहे राहुल जरूर उनके उठाए मुद्दों को सपोर्ट कर देते हैं।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

टिकट मिलने का चांस कम ही लग रहा

दोनों ही स्टार हैं। एक फिल्मों का तो दूसरा क्रिकेट का। दोनों ही बिहार से पार्टी के सांसद हैं। पार्टी नेतृत्व नाराज है तो जाहिर है कि टिकट मिलने का चांस भी कम ही लग रहा है। शत्रुघ्न का तो उम्र का बहाना बना कर भाजपा टिकट काट सकती है, लेकिन कीर्ति के बारे में क्या! कुल मिला कर दोनों की राजनीति चौराहे पर है। चुप रहे तो भी कुछ बनने से रहा, बोलेंगे तो भी निपटेंगे।

कार्पेट बांबिंग के जमाने में आए थे शत्रुघ्न

सबसे पहले बात शत्रुघ्न सिन्हा की। भाजपा के एक बड़े ताकतवर महासचिव हुआ करते थे। नाम था- प्रमोद महाजन। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल रणनीति के तौर पर किया था। शब्द था- कार्पेट बांबिंग। इसके तहत वो क्रिकेट, फिल्मों व अन्य ग्लैमर वर्ल्ड से उन चेहरों को भाजपा में लेकर आए थे, ताकि वे प्रचार कर सकें। लोगों को लुभा सकें। इसी के तहत शत्रुघ्न भी भाजपा में आए थे। तब बिहार में लालू-राबड़ी का शासन था। सोच यह थी कि सुशील मोदी में वह स्टारडम नहीं है, जो शत्रुघ्न में है। वे लालू को हराने का दमखम रखते हैं। ऐसा तब के पार्टी नेतृत्व का मानना था।

आडवाणी के खेमे में बैठे शत्रुघ्न को यह पता नहीं चला कि कब आडवाणी की जमीन खिसक गई। तबतक संघ में मोहन भागवत आ गए थे।

लालू की चुनौती से नहीं निपट सके शत्रु

इसी सोच के तहत उनको बिहार में अहम जिम्मेदारी दी गई थी। स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम लगभग 15 साल तक रहा। अब जाकर हटाया गया है। वाजपेयी सरकार में उनको बड़ा मंत्री पद भी मिला था। बोले तो खूब शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी की रैलियों में। दौड़े भी खूब। पर नतीजा कुछ खास नहीं बदल सका था।

पार्टी यह सब समझती तबतक 2004 का चुनाव आया और भाजपा हार गई। इसके बाद 2005 में बिहार का विधानसभा चुनाव होता है। लालू की हार हुई। लेकिन, इसमें शत्रुघ्न के स्टारडम की कम, नीतीश-मोदी व अन्यों का चातुर्य ही काम आया। मतलब, यदि लालू-राबड़ी राज को राजनेताओं ने खत्म किया तो फिर अभिनेताओं का क्या काम। सुशील मोदी तो आज भी शत्रुघ्न का सीधे-सीधे नाम कम ही लेते हैं।

नीतीश को खास बताते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ

फिर, वाजपेयी नेपथ्य में चले गए। प्रमोद महाजन की मौत हो जाती है। आडवाणी के खेमे में बैठे शत्रुघ्न को यह पता नहीं चला कि कब आडवाणी की जमीन खिसक गई। तबतक संघ में मोहन भागवत आ गए थे और इधर 2009 का चुनाव आडवाणी की भाजपा हार गयी थी। तब भी सुषमा, राजनाथ के साथ शत्रुघ्न आडवाणी खेमे में बने रहे। बदले वक्त में मोदी आए और भाजपा में छा गए।

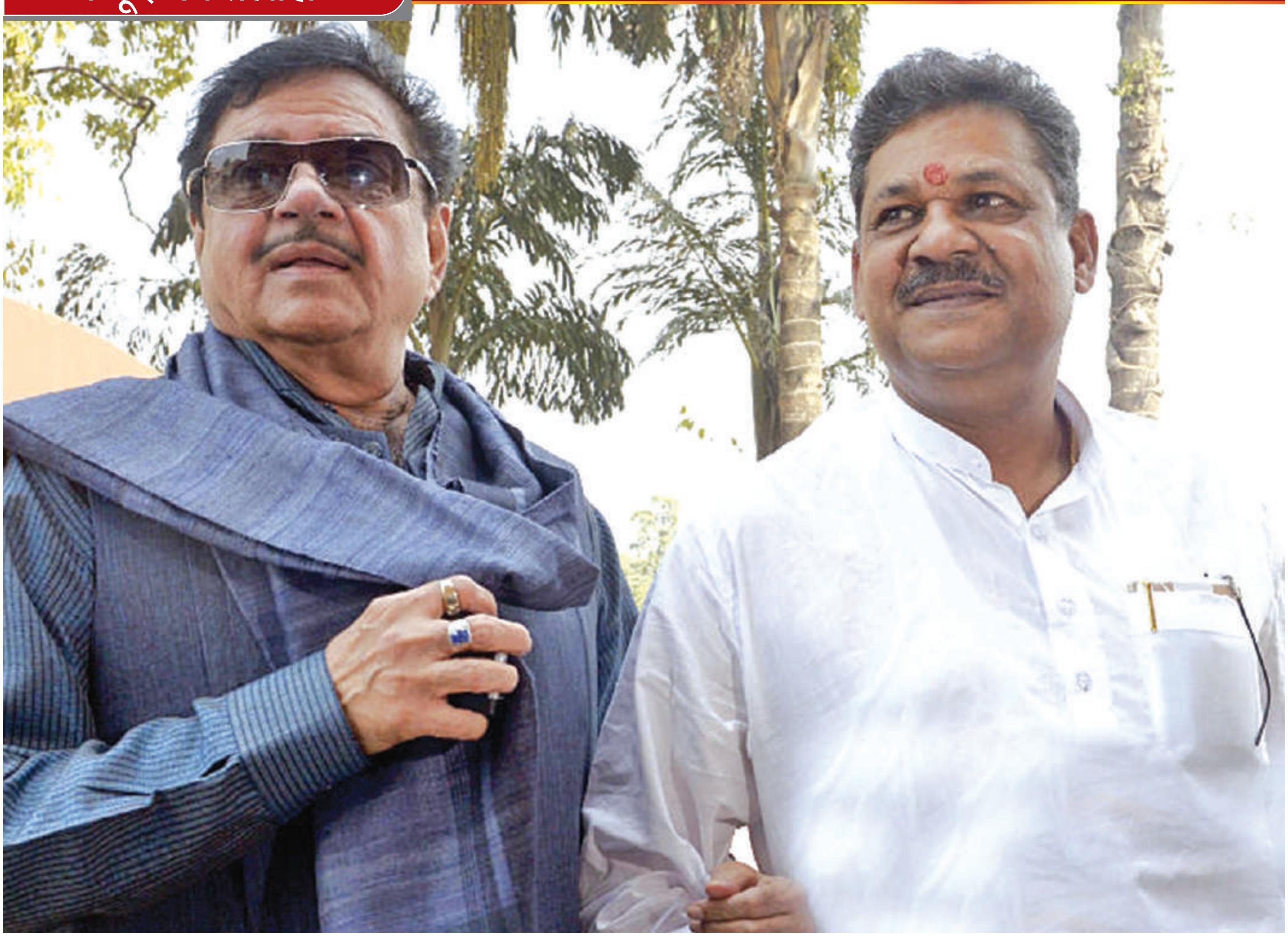

जिस तरह से हाल में कई मंचों पर शत्रुघ्न, यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी के साथ दिखे और बोले, उससे उनकी राजनीति की राह मुश्किल ही होती जा रही है। यह हो सकता है कि वे कांग्रेस का रूख करें।

सरकार बनी 2014 में। शत्रुघ्न को उम्मीद थी कि देर-सबेर मोदी उनको कैबिनेट में जगह देंगे। पर, ऐसा हुआ नहीं। इस बीच जब नीतीश ने एनडीए छोड़ा तब शत्रुघ्न वहां भी पहुंचते रहे और उनसे अपने खास रिश्तों-फ्रेंडशिप की बात मीडिया में दोहराते रहे।

उनको पता तक नहीं चला कि वे धीरे-धीरे मोदी विरोध की लाइन पर चल निकले। बाद में नीतीश जब एनडीए में लौटे तो अब शत्रुघ्न को वहां से भी राजनीतिक तौर पर भाव मिलना बंद हो गया। उसके बाद तो हर मसले पर शत्रुघ्न विपक्ष की भाषा बोलने लगे थे।

जेटली से पंगा लेना भारी पड़ गया कीर्ति को

कुछ ऐसा ही हाल कीर्ति का रहा है। डीडीसीए विवाद के कारण उनकी वित्तमंत्री अरूण जेटली से ठन गई थी। पूरा विवाद मीडिया में लेकर आ गए। उनके मुद्दों का राहुल की कांग्रेस ने समर्थन भी किया। एक वक्त था 2016 में जब कीर्ति के आरोपों की गूंज ही सुनाई देती थी।

यह तो सबको पता है कि जेटली बेहद खास हैं मोदी के लिए। क्योंकि, भाजपा आलाकमान की राजनीति में वे पहले थे, जो मोदी को समर्थन दे रहे थे। ऐसे में पार्टी ने कीर्ति को निलंबित किया। शो-कौज नोटिस भी दिया। हालांकि, बाद में उनके बोल कुछ सुधरे। हां, यह बात भी मौजूं है कि भाजपा में जेटली को कई लोग नापसंद करते हैं, वे सभी कीर्ति का समर्थन करें और उन्हें टिकट मिल जाए।

ऐसी उम्मीद कम ही है पर, अभी तक जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसके मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटना लगभग तय है। उनकी जगह उम्मीदवार खोजा जा रहा है। यदि सुशील मोदी राजी हुए तो ठीक, नहीं तो नितिन नवीन पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। दूसरी ओर, नीतीश सबकुछ दे सकते हैं शत्रुघ्न को, बस अपनी पार्टी से भी टिकट नहीं दे सकते।

जिस तरह से हाल में कई मंचों पर वे यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी के साथ दिखे और बोले, उससे उनकी राजनीति की राह मुश्किल ही होती जा रही है। यह हो सकता है कि वे कांग्रेस का रूख करें। टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन जीत होगी या नहीं, कहना मुश्किल है।

कुछ इसी तरह का हाल कीर्ति का भी है। हां, तारिक अनवर की वापसी के बाद हो सकता है कि भागवत झा आजाद को याद कर राहुल-सोनिया कीर्ति को कांग्रेस में शामिल कर लें, और टिकट भी दे दें। कम से कम कीर्ति ने अपने लिए एक सेफ पैसेज रखा हुआ है। शत्रुघ्न ने तो अपनी राजनीति का सेफ्टी वॉल्व भी कब का निकाल कर फेंक दिया है।

ऐसे में उनका एक और डॉयलॉग भी काफी याद आता है- आप आग के पास रहकर भी शांत नहीं हैं, हम तो दिल में आग रख कर भी बेचैन नहीं हैं। देखते हैं कि आनेवाले समय में शत्रुघ्न 'विश्वनाथ' बनते हैं या कुछ और?

राजनीति की रामलीला

श्रीधर वत्स

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को लेकर जो फैसला पिछले दिनों दिया है, उसके मुताबिक अब इस पर सुनवाई जनवरी से ही शुरू हो सकेगी। लेकिन बीजेपी, आरएसएस सहित कई अन्य हिंदू संगठनों ने देश में महौल बनाना शुरू कर दिया है कि इस मसले का फैसला जल्द से जल्द किया जाए।

वैसे तो हर वर्ष दिसंबर के महीने में अयोध्या का तापमान देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले बढ़ जाता है। लेकिन इस बार पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ता जा रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां संत समाज ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है वहीं राजनेताओं ने भी अपने बयानों से सियासत गरमा दी है। इस लिए अयोध्या में स्थिति एकदम से बदल गई है। अगले कुछ महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर पूरे देश में सियासत तेज है कोशिश की जा रही है किस मुद्दे को मई में होने वाले चुनाव तक गरमा कर रखा जाए ताकि इसका सियासी फायदा उठाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को लेकर जो फैसला पिछले दिनों दिया है, उसके मुताबिक अब इस पर सुनवाई जनवरी से ही शुरू हो सकेगी। लेकिन बीजेपी, आरएसएस सहित कई अन्य हिंदू संगठनों ने देश में महौल बनाना शुरू कर दिया है कि इस मसले का फैसला जल्द से जल्द किया जाए।

बयानबाजी तो ठीक है, पर कैसे बनेगा राम मंदिर?

अयोध्या में चल रहे आंदोलन के बीच संघ नेताओं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों के बाद अयोध्या में सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मंदिर बनेगा तो कैसे? सरकार के पास क्या कानूनी विकल्प है? अध्यादेश लाने की लगातार मांग के बीच सरकार के एक धड़ा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगा है। सरकार के इस धड़े का मानना है कि बिना अध्यादेश भी मंदिर का काम शुरू किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। संविधान विशेषज्ञ भी सरकार के इस धड़े की बात से सहमति जता रहे हैं।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप की मानें, तो सरकार गैर विवादित जमीन पर जब चाहे मंदिर का निर्माण शुरू करा सकती है। इसके लिए सरकार को सिफ गैर-विवादित जमीन को मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट को स्थानांतरित करनी है, निर्माण का काम शुरू होने के बाद सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती है।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप की मानें, तो सरकार गैर विवादित जमीन पर जब चाहे मंदिर का निर्माण शुरू करा सकती है। इसके लिए सरकार को सिफ गैर-विवादित जमीन को मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट को स्थानांतरित करनी है।

अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एमएल लोहाटी की राय थोड़ी अलग है। लोहाटी का मानना है कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, तो ऐसे में सरकार को अध्यादेश लाने से बचना चाहिए। हालांकि, वो मान रहे हैं कि सरकार के पास अध्यादेश लाने का पूरा अधिकार है और सरकार जब चाहे अध्यादेश ला सकती है।

सरकार के अंदर के सूत्रों की मानें, तो अगर अध्यादेश लाना भी पड़ा तो वह बजट सत्र के बाद ही लाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर से पहले अध्यादेश लाने पर बजट सत्र में उसे पास कराने की चुनौती होगी और बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा।

बजट सत्र के बाद अध्यादेश लाने पर सरकार के पास अगले चुनाव में जाने से पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू कराने का मौका होगा। चुनाव से पहले अध्यादेश को कानून बनाने की जिम्मा इस सरकार के जिम्मे नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने राम मंदिर का निर्माण पूरा कराने के नाम पर वोट मांगने का पूरा मौका होगा।

अमित शाह साधु-संतों के साथ करेंगे मीटिंग!

बीजेपी के सूत्रों की मानें तो अध्यक्ष अमित शाह नंवबर के अंतिम सप्ताह में राम मंदिर मुद्दे पर साधु-संतों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। इससे पहले अखिल भारतीय संत समिति के धर्मादेश सम्मेलन में संतों ने राम मंदिर पर धर्मादेश दिया था। धर्मादेश सम्मलेन में संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। बता दें मंदिर निर्माण के संबंध में आरएसएस के बाद अब साधु-संतों ने सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए धर्मादेश जारी करते हुए कहा है कि अध्यादेश लाएं या फिर कानून बनाएं लेकिन निर्माण कार्य आम चुनाव से पहले शुरू होना चाहिए।

धर्मादेश सम्मेलन में साधु-संतों ने कहा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं और सब्र टूट रहा है। केंद्र सरकार को हर हाल में आम चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होना चाहिए। सम्मेलन में राम मंदिर निर्माण को लेकर पारित प्रस्ताव के मुताबिक, 'यह केंद्र सरकार का काम है कि मंदिर अध्यादेश से बने या कानून से।'अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जीतेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, ‘संत समाज मंदिर निर्माण के लिए सरकार से आग्रह नहीं कर रहा है, यह आदेश है। संत और बहुसंख्यक हिंदू समाज चुनाव से पहले हर हाल में राम मंदिर का निर्माण चाहता है। इसके अध्यादेश लाना या सौहार्दपूर्ण माहौल में रास्ता निकालना सरकार का काम है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते।

मंदिर था, है और रहेगा: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम की भव्य मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की है, जो अयोध्या की पहचान बनेगी। उन्होंने यह फैसला फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करने के दूसरे दिन लिया।

मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रिपोर्टरों से कहा कि उन्होंने दो जगहों को राम मूर्ति स्थापित करने के लिए चुना है।

योगी ने कहा कि मूर्ति निर्माण कराने पर वह विचार कर रहे हैं। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में आर्किटेक्टों से कई सुझाव मंगाए गए हैं।

अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''आपको पता है कि अयोध्या में पहले से ही एक मंदिर है. मंदिर था, है और रहेगा। सभी विकल्प खुले हैं लेकिन समाधान कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए निकाला जाएगा।

1992 जैसा करेंगे आंदोलन: भैयाजी जोशी

पिछले दिनों मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के बाद संघ के सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा कि अगर जरुरत पड़ेगी तो हम एक बार फिर 1992 जैसा आंदोलन करेंगे। भैयाजी जोशी ने कहा कि अयोध्या को लेकर पिछले 30 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, सामूहिक रूप से समाज की अपेक्षा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। इसमें कानूनी बाधाएं हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला देगा। लेकिन कोर्ट के जरिए भी इसके निर्माण में बहुत देरी हो रही है, 2010 में इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब मामला 3 सदस्य पीठ के पास पहुंचा, हम चाह रहे थे कि दिवाली से पहले कुछ शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया है, ये उनका अधिकार है।

उन्होंने कहा कि जब कोर्ट से पूछा गया कि इसके बारे में आप कब बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अलग है। इस बात से हमें दुख पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट के जवाब से हिंदू समाज अपमानित महसूस करता है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जल्द से जल्द सुनें।

हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की उपेक्षा नहीं है, लेकिन न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों की भावनाओं का सम्मान करे। अगर कोई विकल्प नहीं बचता है, तो सरकार को इस पर भी विचार करना ही पड़ेगा।

हालांकि, संघ के इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट हिंदू भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दे सकता है। संघ अब भी इस बात से इनकार कर रहा है कि देश में कोई संविधान है। यहां आस्था, भावना नहीं बल्कि इंसाफ ही चलता है।'

ओवैसी के अलावा कांग्रेस ने भी संघ के बयान पर जवाब दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इन लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का ठेका नहीं ले रखा है, संघ और बीजेपी अपनी विफलताओं का ठीकरा सुप्रीम कोर्ट पर ना थोपे।

मंदिर निर्माण दो ही रास्तों से हो सकता है। पहला सुप्रीम कोर्ट और दूसरा बातचीत, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है। वह किस फैसले की राह देख रहे हैं, जब अभी तो सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। संघ और बीजेपी लोगों को झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोर्ट को धमकाया था।

वहीं, बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी संघ के इस बयान पर कमेंट किया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेता बेशक लगातार बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन हमारा रुख साफ है कि मंदिर निर्माण दो ही रास्तों से हो सकता है। पहला सुप्रीम कोर्ट और दूसरा बातचीत, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

केसी त्यागी बोले कि आरएसएस-बीजेपी को अपने-अपने विचार के हिसाब से और आस्था के हिसाब से बात रखने का अधिकार है। हम संसद से कानून लाने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए सभी को सर्वोच्च अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बहरहाल, इसके बावजूद बीजेपी नेताओं के बयान अयोध्या विवाद पर थमे नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'राम मंदिर जरूर बनेगा। कांग्रेस अभी तक इस मामले को लटकाने का काम करती आई है। अब हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है। मुझे भय है कि अगर हिन्दुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा?'

उधर, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, 'मुझे लगता है कि हमें यह देखने के लिए दिसंबर में एक रिव्यू करना चाहिए कि राम मंदिर के मामले को जल्दी से स्थगित कर दिया जा रहा है या फिर कांग्रेस के वकीलों को इस मामले में देरी के लिए कुछ अन्य विषयों का आवेदन मिलेगा। यदि इसमें देरी हो रही है तो हमें कुछ करना होगा।'

राम जन्मभूमि को लेकर संघ के विचारक इंद्रेश कुमार का कहना है कि जैसे काबा को बदला नहीं जा सकता, हरमंदिर साहब को बदला नहीं जा सकता, वेटिकन और स्वर्णमंदिर नहीं बदला जा सकता, वैसे ही अयोध्या में रामजन्मभूमि का स्थान नहीं बदल सकता है। यह एक सत्य है।

उद्धव ठाकरे भी अयोध्या में फूंकेंगे सियासी बिगुल

शिवसेना ने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी चाल चल दी है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व कार्ड के साथ ही उत्तर भारत में अपनी सियासी दखल बढ़ाना चाहते हैं।

राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है, हर राजनीतिक दल इस पर अपने तरीके से बयानबाजी कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिव सेना ने भी सियासी चाल चल दिया है।

25 नवंबर को अयोध्या में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की रैली से पहले उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां पर डेरा डाल दिया है। उद्धव के दौरे से पहले सांसद संजय राउत समेत पार्टी के कई नेताओं ने यहां पहुंचकर संत समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। राउत ने बताया है कि अपने प्रवास के दौरान उद्धव ठाकरे अयोध्या विवाद से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत करेंगे।

देखा जाय तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीते दिनों केंद्र सरकार पर राम मंदिर के निर्माण में देरी करने का आरोप लगाते हुए 25 नवंबर को अयोध्या में रैली करने और रामलला के दर्शन करने की घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे पार्टी प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने संत समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

संजय राउत ने यह भी कहा कि संतो के साथ उद्धव ठाकरे की भी इच्छा है कि सरकार कानून बनाकर मंदिर का निर्माण कराए क्योंकि न्यायालय से राम मंदिर का निर्माण हो पाना मुश्किल है।

इसी मामले को लेकर उद्धव ठाकरे आगामी 24 नवंबर को यहां पहुंच रहे हैं और इस दौरान वह यह मामले से जुड़े सभी पक्षकारों से बात करेंगे। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को उद्धव अयोध्या में एक रैली भी करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। उद्धव के बगावती तेवरों के बावजूद यूपी सरकार ने अभी तक उनके कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई है।

वहीं उद्धव के कार्यक्रम के रोज ही विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी अयोध्या में एक विशाल रैली करने की घोषणा की गई है। इस रैली के लिए सोमवार को ही वाराणसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के तमाम प्रचारकों के साथ बैठक की है।

झारखण्ड
निर्माण के
18 वर्ष
झारखण्ड
स्थापना दिवस
की सभी
प्रदेशवासियों को
हार्दिक बधाई...
निवेदक
जयकांत कुमार कश्यप
आजसू नगर अध्यक्ष सह युवा प्रदेश महासचिव, तेली महासभा (झारखण्ड) खूंटी

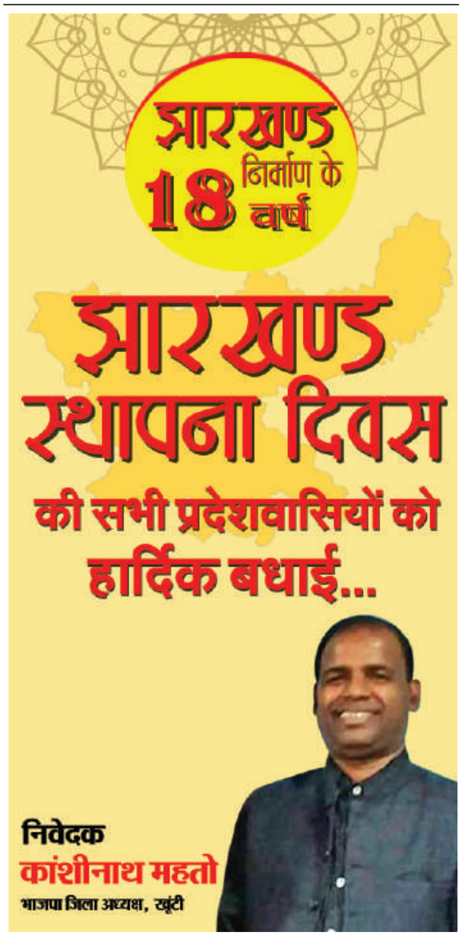

गरीबों की सेवा करने के लिए ही राजनीति में हूं- जयकांत

खूंटी की सियासत में जयकान्त कुमार कश्यप के नाम से हर कोई परिचित है। उन्होंने बहुत ही कम समय में लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है।

खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र की जनता की हर समस्या का समय पर और हर हाल में समाधान हो इसके लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। गरीबों की सेवा करना, उनकी मदद करना ही उनकी राजनीति का मुख्य मकसद रहा है।

जयकांत कश्यप ने जब से आजसू पार्टी का दामन थामा है वे लगातार जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर कर उसके समाधान के लिए आन्दोलन करते रहे हैं, चाहे बिजली की समस्या हो या नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की। इन सभी मुद्दों पर खूब बढ़-चढ़कर उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है।

जयकान्त कुमार कश्यप आजसू पार्टी के अलावा प्रदेश तेली समाज उत्थान संगठन के महासचिव भी हैं। पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर वे कई बार आन्दोलन का नेतृत्व कर चुके हैं।

जयकान्त कहते हैं कि वर्तमान समय में लोग राजनीति में स्वार्थहित को आगे रखकर ही काम करते हैं। वे जनता और कार्यकर्ताओ की समस्या के प्रति सजग नहीं रहते। कई लोग तो ऐसे हैं जो धोखा देने काम करते हैं।

जयकांत कहते हैं कि जबकि लोगों को समझना चाहिए कि राजनीति एक सेवा है, लेकिन सेवा के बदले उन्हें, मेवा खाने की जल्दी होती है। ऐसे लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं और अफसरों की दलाली करते हैं। जबकि जनता उन पर विश्वास करती है लेकिन वे जनता को धोखा देने का काम करते हैं।

वो आगे कहते हैं कि मेरा तो यही मनना है कि राजनीति जनता की सेवा करने और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम है। इससे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भविष्य में ऊंचा मुकाम मिल सकता है। वह मुकाम स्थायी और टिकाऊ होगा। साथ ही समाज में सम्मान भी मिलेगा।

जयकांत कहते हैं कि मैं 2015 से राजनीति में हूं। सबसे पहले झारखंड पार्टी से जुड़ा, एनोस एक्का के साथ मिलकर मैंने चुनाव में उनका सहयोग किया। उसके बाद 2016 में आजसू की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर आजसू से जुड़ गया। पार्टी ने मुझे खूंटी नगर अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी। इस जिम्मेवारी को मैंने बखूबी निभाया और आजतक निभाता आ रहा हूं। मैंने आरक्षण, बिजली, पानी, होल्डिंग टैक्स के साथ ही घर-घर में लाल कार्ड, पीला कार्ड ग्रामीणों को दिलाने का काम किया। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मैं सतत प्रयास करता रहा हूं।

जयकांत कहते हैं कि मेरे प्रयास से 10- 11 युवाओं को कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिली है। खूंटी को नशामुक्त करने के लिए हर स्तर पर मेरी कोशिश जारी है, इसके लिए सरकारी स्तर पर जो भी सहायता मिल सकती है उसके लिए भी प्रयासरत हूं।

झारखण्ड निर्माण के 18 वर्ष
झारखण्ड स्थापना दिवस
की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई...
निवेदक
रामकृष्ण चौधरी
जिला अध्यक्ष, कांग्रेस, खूंटी

झारखण्ड निर्माण के 18 वर्ष
झारखण्ड स्थापना दिवस
की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई...
निवेदक
जुबेर अहमद
जिला अध्यक्ष
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
खूंटी

झारखण्ड निर्माण के 18 वर्ष
झारखण्ड स्थापना दिवस
की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई...
निवेदक
महेंद्र राम
कार्यपालक
पदाधिकारी, खूंटी

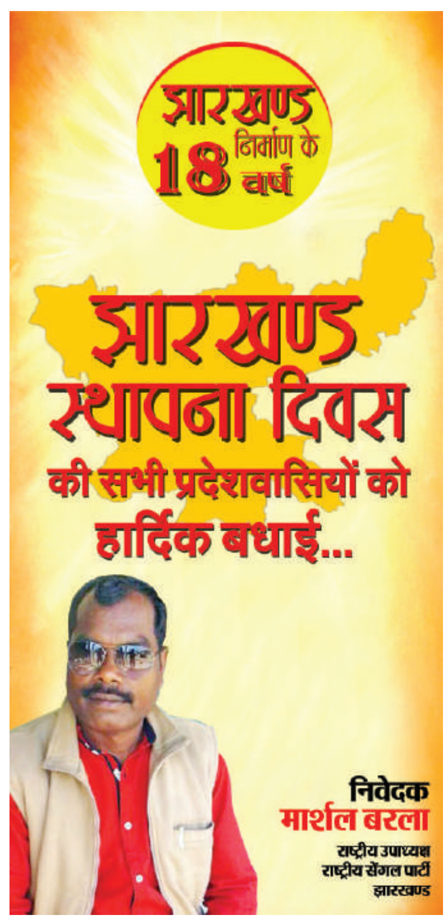
झारखण्ड निर्माण के 18 वर्ष
झारखण्ड स्थापना दिवस
की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई...
निवेदक
मार्शल बरला
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय सेंगल पार्टी
झारखण्ड

भुवनेश्वर यादव
मुख्य संरक्षक
उदय प्रताप सिंह यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष
सत्यप्रकाश सिंह यादव
राष्ट्रीय मुख्य महासचिव
अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ESTD 1924 ALL INDIA YADAV MAHASABHA
कमला यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला)
दिनेश यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा)
बजरंगी प्रसाद यादव
कार्यकारी अध्यक्ष
स्वागताध्यक्ष
अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
स्थानः गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, चिरौंदी, टैगोर हिल रोड,
मोरहाबादी, रांची.
दिनांकः 18 नवंबर 2018, दिन रविवार
पीतांबर दास
प्रदेश अध्यक्ष
मीरा कुमारी राय
प्रदेश अध्यक्ष (महिला)
अनिल यादव
प्रदेश अध्यक्ष (युवा)
सिद्धार्थ घोष
प्रमुख महासचिव
आयोजकः- प्रांतीय यादव महासभा झारखंड
रमेश प्रसाद यादव
उपाध्यक्ष
राजकिशोर प्र. (पप्पू यादव)
उपाध्यक्ष
आनंदमय पात्रा
उपाध्यक्ष
राजेश्वर प्रसाद यादव
उपाध्यक्ष
सुदर्शन सिंह यादव
उपाध्यक्ष
डॉ. मेधावती आर्या
उपाध्यक्ष
अनुराग कु. मंडल
महासचिव
रामाशीष यादव
महासचिव
विर्जेंद्र यादव
महासचिव
कृष्णा सिंह यादव
महासचिव
सुरेश गोप
महासचिव
पुनीता यादव
महासचिव
रामेश्वर प्र. यादव
अध्यक्ष, उ. छोटानागपुर
सविता गोप
महासचिव
उ. छोटानागपुर
सुधीर गोप
अध्यक्ष, महानगर
तपेश्वर यादव
अध्यक्ष, रांची जिला
दिलेश्वर गोप
कोषाध्यक्ष
बली यादव
अध्यक्ष, पलामू प्रमंडल

प्रान्तीय यादव महासभा झारखंड

प्रदेश के यादव समाज की एकता और समाज की बेहतरी के लिए सतत प्रयत्नशील

समाज के युवा वर्ग के लिए उपयुक्त सामाजिक, शैक्षणिक माहौल बनाने की प्रतिबद्धता

देवघर में महान शिवभक्त बाबा बैजू की मूर्ति स्थापना हेतु प्रयासरत

पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण के हक की लड़ाई

बजरंगी प्रसाद यादव

कार्यकारी अध्यक्ष, प्रान्तीय यादव महासभा झारखंड

कोर कमिटी

अध्यक्ष
श्री बजरंगी प्रसाद यादव

सचिव- श्री सिद्धार्थ घोष

सदस्य- श्री आनंदमय पात्रा, श्री रमेश प्रसाद यादव, श्री डॉ. मेघावती आर्या, श्री राजकिशोर यादव, श्री अनुराग कुमार मंडल, श्री रामाशीष यादव, श्री कृष्णा सिंह यादव, श्री मीरा कुमारी राय, श्री अनिल यादव, श्री दिलेश्वर गोप, श्री रामेश्वर प्रसाद यादव

आर्मंत्रित सदस्य

श्री बिजेन्द्र यादव, श्री सुरेश गोप, श्री सुधीर गोप, श्री प्रदीप यादव

गरिमामय उपस्थिति

श्री भुवनेश्वर यादव
श्री पिताम्बर दास

प्रान्तीय यादव महासभा झारखंड की प्रदेश कार्यकारिणी समिति

मुख्य संरक्षक:- श्री भुनेश्वर यादव
अध्यक्ष:- श्री पीताम्बर दास
कार्यकारी अध्यक्ष:-
श्री बजरंगी प्रसाद यादव

उपाध्यक्ष:- श्री आनन्द मय पात्रा, श्री रमेश प्रसाद यादव, श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, श्री सुदर्शन सिंह यादव, डॉ. मेघावती आर्य, श्री राजकिशोर यादव

प्रमुख महासचिव:- श्री सिद्धार्थ घोष

महासचिव :- श्री अनुराग कुमार मंडल (पलामू), श्री रामाशीष यादव (युवा), श्री बिजेन्द्र यादव (मुख्यालय), श्री कृष्णा सिंह यादव (संथाल), श्री सुरेश गोप (द. छोटानागपुर), श्री सारंगीधर गोपाल (कोलहान) श्री छोटेलाल यादव (उत्तरी छोटानागपुर), श्रीमती पुनीता यादव (महिला)

सचिव :- श्री कमल यादव (देवघर, जामताड़ा, दुमका), श्री राजेश यादव (साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा), श्री चंद मोहन महतो (खूंटी, रांची, गुमला), श्री कुवंर गोप (सिमडेगा, लोहरदगा), श्री विनोद यादव (पू.सिंहभूम, प. सिंहभूम, सरायकेला), श्री लालमुनी यादव (धनबाद, बोकारो, रामगढ़), श्री मनोज कुमार यादव (हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा), श्री सत्य नारायण यादव (लातेहार, पलामू, गढ़वा)

कोषाध्यक्ष :- श्री दिलेश्वर गोप

कार्यकारिणी सदस्य:- श्री बुधन यादव (बोकारो), श्री अरुण कुमार यादव (चतरा), श्री सुंदर यादव (धनबाद), श्री राकेश यादव (दुमका), श्री छोटू सिंह यादव (गिरिडीह), श्री कृष्ण प्रसाद यादव (गढ़वा), श्री चुनचुन यादव (गोड्डा), श्री तुलसी दास यादव (गुमला), श्री उमेश गोप (हजारीबाग), श्री गौरचन्द्र यादव (जामताड़ा), श्री लालदेव यादव (कोडरमा), श्री लाल मोहन यादव (खूंटी), श्री वृंदविहारी यादव (लातेहार), श्री देवनाथ गोप (लोहरदगा), श्री अशोक यादव (पाकुड़), श्री अजय यादव (पलामू), श्री तपेश्वर यादव (रांची), श्री सुधीर गोप (रांची महानगर), श्री हीरा गोप (रामगढ़), श्री हरे कृष्ण प्रधान (सरायकेला), श्री भरत यादव (साहेबगंज), श्री दिनेश्वर यादव (सिमडेगा), श्री अनवेश्वरी प्रधान (प. सिंहभूम), श्रीमती मीरा कुमारी राय, प्रदेश अध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ), श्री अनिल यादव प्रदेश अध्यक्ष (युवा प्रकोष्ठ), ललित यादव, अध्यक्ष (विधि प्रकोष्ठ), डॉ. विजय कुमार यादव, अध्यक्ष (बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ), मनरखन गोप, अध्यक्ष (द. छोटानागपुर प्रमंडल), रामेश्वर प्रसाद यादव, अध्यक्ष (उ. छोटानागपुर प्रमंडल), श्री प्रदीप यादव, अध्यक्ष (संथाल प्रमंडल), श्री बली यादव, अध्यक्ष (पलामू प्रमंडल), श्रीमती सबिता गोप, महासचिव (उ. छोटानागपुर प्रमंडल), श्री अशोक यादव, महासचिव (संथाल प्रमंडल), श्री शिवपूजन यादव, महासचिव (पलामू प्रमंडल), श्री लखन गोप, महासचिव, (द. छोटानागपुर प्रमंडल)

आमंत्रित सदस्य:- श्री विजय घोष, श्री बासुकी यादव, श्री हरिप्रसाद यादव, श्री सुख रंजन घोष, श्री सिद्धिनाथ सिंह यादव, श्री सुरेश गोप, श्री अर्जुन गोप, श्री महावीर गोप, श्री केदार गोप (रांची), श्री अजय यादव (गढ़वा), श्री मुकेश यादव (देवघर), श्री हेमंत कुमार यादव (जामताड़ा), श्री दिगंबर प्रसाद यादव (गिरिडीह), श्री नरेंद्र कुमार यादव (लोहरदगा)

पिछड़ों की आवाज... **संगठित यादव समाज...**